卐 श्री सदगुरू देवाय नम: 卐 卐 ओ३म् 卐 卐 जय माता दी 卐
卐 सीताराम बाबा जी 卐卐 जय बाबा की 卐卐 श्याम बाबा 卐 卐
卐 ! जाके सुमिरन तें रिपु नासा!! ! नाम सत्रुहन बेद प्रकासा!! 卐

उल्लंघ्य सिन्धो: सलिलं सलीलं,य:शोकवह्नि जनकात्मजाया: आदाय तेनैव ददाह लंकां,नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्
मनोजवं मारुत तुल्य वेगं,जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये

केन्द्र व उत्तरांचल सरकार से विज्ञापन मान्यता प्राप्त

हिन्दी सान्ध्य दैनिक

उत्तरांचल दर्पण

♦वर्ष 26 ♦अंक 53 ♦पृष्ठ 8 ♦रुद्रपुर(ऊधमसिंहनगर) ♦शनिवार ♦29 नवम्बर 2025 ♦मूल्य दो रूपया

darpan.rdr@gmail.com 9897427585 UTTARANCHAL DARPAN www.uttaranchaldarpan.in

GAGNEJA PROPERTIES
CONTACT FOR SALE, PURCHASE RENT & LEASE
✔ Shops ✔ Houses
✔ Industrial Property
✔ Commercial Property
✔ Agriculture Land
REAL ESTATE WITHOUT THE HASSLE
MO.-8630672525,8279444462
ADD- SRA F69, Shop No.4, Adarsh Colony, Rudrapur

दिल्ली ब्लास्ट में बनभूलपुरा से इमाम गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार रात ढाई बजे हल्द्वानी में स्थित बिलाली मस्जिद में दी दबिश

हल्द्वानी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकवादी उमर से जुड़े कॉल डिटेल्स की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार रात ढाई बजे हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में स्थित बिलाली मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार किया। टीम संदिग्ध को पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई है। दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकवादी उमर से जुड़े मोबाइल के कॉल डिटेल को खंगालने में दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली है। शुक्रवार की देर रात ढाई बजे दिल्ली पुलिस की

स्पेशल टीम के साथ ही एलआईयू दिल्ली की टीम ने हल्द्वानी के संवेदनशील मुस्लिम बाहुल्य इलाके बनभूलपुरा में दबिश देकर बिलाली मस्जिद के इमाम को उठाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस उसे लेकर दिल्ली चली गई। उधर दबिश के बाद क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए सुबह ही एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल के साथ ही सीओ लालकुआं दीपशिखा अग्रवाल के अलावा, लालकुलां, कालाढूंगी, हल्द्वानी, मुखानी, काठगोदाम थाना की पुलिस बनभूलपुरा पहुंच गई। अचानक से फोर्स देखकर स्थानीय लोग भी सहम गए। पुलिस ने बिलाली मस्जिद तथा इसके बगल में स्थित इमाम के आवास पर कड़ी सुरक्षा रखी है। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई की है। एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था। आतंकी हमले में दर्जन भर से अधिक लोगों की जान गई थी और (**शेष पेज 7 पर**)

समाज कल्याण का कार्य ही सबसे बड़ा धर्म–धामी

अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंचने पर मुख्यमंत्री धामी का हुआ जोरदार स्वागत

कुरुक्षेत्र। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुरूक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का शास्वत उपदेश दिया था। उन्होंने कहा कि वहीं श्री भागवत गीता के रूप में मानवता का शास्वत ज्ञान बनकर पूरे विश्व का मार्ग दर्शन कर रही है। इस पावन धरा को वह दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। कुरूक्षेत्र के पुरूषोत्तमपुरा बाग में आयोजित संत सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये श्री धामी ने कहा गीता कर्म का संदेश देते है। कर्मण्येवाधिकारस्त मा फलेषु कदाचन, यह एक लाईन मुझे याद है। उन्होंने आगे कहा कि समाज के कल्याण (**शेष पेज 7 पर**)

ट्रक की टक्कर से गिरे युवक को बस ने कुचला

दिनेशपुर(उद संवाददाता)। गदरपुर मटकोटा मार्ग पर शुक्रवार देर शाम एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इससे युवक बाइक समेत सड़क पर

गिर गया। तभी पीछे आ रही बस ने युवक को बुरी तरह से कुचल दिया। हादसे में मौके पर ही युवक की मौत हो गई। ट्रक और बस चालक वाहन (**शेष पेज 7 पर**)

अपराधियों का गढ़ बन रहा ठंडा नाले के अतिक्रमण पर चली जेसीबी

धामी सरकार ने चलाया बल्डोजर ,यूपी से आए लोगों ने अवैध कब्जा कर अपने मकान बना लिए

गूलरभोज(उद संवाददाता)। जिस स्थान पर उत्तराखंड पुलिस के छापा मारने में पसीने छूट जाते थे। वो अपराधियों की शरणस्थली ठंडा नाला आज धामी सरकार के बुलडोजरों ने ध्वस्त कर दिया। दिनेशपुर गूलरभोज के बीच ठंडा नाला वो सरकारी जगह है जहां यूपी से आए लोगों ने अवैध कब्जा कर अपने मकान बना लिए। सिंचाई विभाग और वन विभाग की इस भूमि पर सौ से ज्यादा अतिक्रमण है जिनमें से आज करीब 30 कच्चे पक्के मकानों को उधम सिंह नगर प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगा कर मिट्टी में मिला दिया। डीएम नितिन भदौरिया के निर्देश पर एडीएम पंकज उपाध्याय, प्रशासनिक अधिकारी ऋचा सिंह के नेतृत्व में आज तड़के से ही अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ। प्रशासन ने यहां अवैध कब्जों पर एक माह पूर्व नोटिस जारी किया था और कब्जेदारों को सरकारी भूमि खाली करने का वक्त देते हुए मुनादी भी करवाई थी। बीते कल ही कुछ कब्जेदारों ने अपने अतिक्रमण हटाने और अपना सामान निकालना शुरू कर दिया था। आज करीब तीस भवनों को जमींदोज करते हुए प्रशासन की टीम लौट गई। शेष अन्य अतिक्रमण पर आगे कारवाई शुरू की (**शेष पेज 7 पर**)

चोरों ने बंद घर खंगाल लाखों के जेवर और नगदी उड़ाई

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित गोपाल विहार में अज्ञात चोरों ने परिजनों की गैर मौजूदगी में घर के ताले तोड़ अलमारी में रखे लाखों रूपये

कीमत के जेवरात और हजारों की नगदी उड़ा ली। पड़ोसियों से मामले की जानकारी मिलने पर गृहस्वामी वापस लौटा और उसने घटना की सूचना (**शेष पेज 7 पर**)

रुद्रपुर नगर निगम पार्षदों को मिलेगी फोन बिल की सुविधा

मेयर विकास शर्मा की पहल का पार्षदों ने किया स्वागत

रुद्रपुर। नगर निगम रुद्रपुर ने पार्षदों के हित में एक बड़ा और जनसेवा उन्मुख निर्णय लेते हुए सभी पार्षदों के मोबाइल फोन का बिल अब निगम द्वारा वहन करने की घोषणा की है। यह सुविधा वर्तमान बोर्ड के पूरे कार्यकाल तक जारी रहेगी। मेयर विकास शर्मा की इस पहल का पार्षदों के साथ–साथ आम जनता ने भी स्वागत किया है। मेयर शर्मा ने कहा कि मैंने अपने पार्षदों के हित के लिए एक और कदम बढ़ाया है और उन्हें मुफ्त मोबाइल बिल की सुविधा दी है, ताकि वे अपने क्षेत्र की जनता के लिए और

अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकें। मेयर ने बताया कि सभी पार्षदों को उनके मौजूदा मोबाइल नंबरों पर ही पोस्टपेड प्लान में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसमें अनलिमिटेड डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। इसका पूरा खर्च नगर निगम वहन करेगा। उन्होंने कहा कि पार्षदों को अपने क्षेत्र की समस्याओं और जनता के मुद्दों पर लगातार संवाद बनाए रखना पड़ता है, जिसके लिए मोबाइल फोन एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे में उनका यह आर्थिक बोझ कम करना आवश्यक था। मेयर विकास शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह सुविधा बिना किसी भेदभाव के सभी पार्षदों को दी जा रही है। उन्होंने कहा, हमने पार्षदों पर अतिरिक्त आर्थिक भार डालने के बजाय उनकी सुविधा सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। पार्षद जनता के सबसे निकट रहने वाले जनप्रतिनिधि हैं, जो बिना किसी अपेक्षा के दिन–रात जनता की समस्याओं के समाधान में लगे रहते हैं। इसलिए उनकी कार्यशैली को मजबूत करना और उन्हें बेहतर साधन उपलब्ध कराना नगर निगम की जिम्मेदारी है। उन्होंने आगे कहा कि इस कदम से पार्षदों और जनता के बीच संवाद और अधिक सहज व त्वरित होगा। विकास शर्मा ने (**शेष पेज 7 पर**)

पर्यावरण चुनौतियां तथा पर्यटन संभावनाओं विषय पर हुआ 'विमर्श'

सुरक्षा का राष्ट्र प्रथम बोध से, पर्यावरण का सजगता और पर्यटन का अतिथि देवो भव: की अवधारणा को आत्मसात करके करना होगा उपचार- राज्यपाल

देहरादून(उद संवाददाता)। राजभवन सभागार में उत्तराखण्ड में सुरक्षा और पर्यावरण चुनौतियां तथा पर्यटन विषय पर विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि हमें आज संकल्प लेना है कि हम उत्तराखण्ड में द्वितीय पंक्ति के सुरक्षा प्रहरी के रूप में सेवा करेंगे, पर्यावरण की रक्षा के लिए हम देवभूमि के प्राचीन संतों की तरह आचरण करेंगे तथा पर्यटन के उत्थान में हम अतिथि देवो भव: की अवधारणा को आत्मसात करेंगे। विशेष कर युवाओं और पूर्व सैनिकों को इसका दृढ़ निश्चय होकर संकल्प लेना चाहिए। मन में सभी को यह गांठ बांध लेनी चाहिए कि यदि राष्ट्र होगा तो समाज होगा, समाज होगा तो परिवार होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि किस प्रकार से मुगलों और अंग्रेजों ने हमारे स्वाभिमान और हमारे मूल्यों पर कुठाराघात किया। इसलिए हमें एकता और आपसी तालमेल से राष्ट्र के उत्थान और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करना होगा। इसीलिए हमें अपनी चुनौतियों, अपनी खूबियों और अपनी मर्यादा की सीमा पता होनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि 2014 के बाद हमारी टॉप लीडरशिप ने आत्मनिर्भर भारत, सशक्त और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में लगातार मजबूती से और दृढ़ता से ठोस निर्णय लिए हैं। आज हमारे पास प्रभावी और मजबूत लीडरशिप है, युवा शक्ति की मैन पावर है और मेहनती लोग हैं। इसीलिए हमें विकसित भारत निर्माण के संबंध में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के सर्वांगीण विकास के लिए पांच क्रांति की जरूरत है- हनी क्रांति, एरोमा क्रांति, मिलेट क्रांति, स्वयं सहायता समूह क्रांति और होमस्टे क्रांति। लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने उत्तराखण्ड के विशेष संदर्भ में सुरक्षा क्रियान्वयन विषय पर संबोधन के दौरान कहा कि चीन-पाक गठजोड़, बांग्लादेश की पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकी, सीमा पर तस्करी, साइबर हमले, नकारात्मक सोशल मीडिया, देश विरोधी टूलकिट, नकारात्मक प्रचार हमारी बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के सबसे बड़े खतरे हैं। आंतरिक खतरों से निपटने के लिए उन्होंने भारतीय जन समुदाय को प्रशिक्षित सुशिक्षित और जागरूक रहने तथा देश के प्रति निष्ठा, समर्पण और सेवाभाव को आत्मसात करने की अपील की। मैती आंदोलन के प्रणेता पदमश्री कल्याण सिंह रावत ने पर्यावरण विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि बांझ उत्तराखण्ड के पर्यावरण के केंद्र में है। अंग्रेजों ने कोयला बनाने के लिए बांझ के पेड़ों पर आरी चलाई तथा इसके स्थान पर रेजिन और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए चीड़ की विदेशी प्रजातियां लगाई। आज यहां बांझ के पेड़ सिमटकर 14 प्रतिशत के आसपास रह गए हैं जबकि चीड़ के पेड़ 27 प्रतिशत से ऊपर पहुंच चुके हैं। बांझ के पेड़ घटे तो पहाड़ों में जल स्रोत सूख गए, जंगल में नमी कम हो गई, जिससे वन्य जीवों को ना तो जंगल में ना तो हरियाली मिल रही और न ही पीने को पानी, जिससे जंगली जानवर आबादी की ओर पलायन कर रहे हैं। परिणाम स्वरुप मानव- वन्य जीव संघर्ष हो रहा है। चीड़ का पेड़ इस तरह से घुसपैठ कर चुका है कि स्थानीय देसी प्रजातियां सब गायब हो रही हैं। जंगल में आग लगने का सबसे बड़ा कारण भी चीड़ का ही पेड़ है। जंगल जलने से ब्लैक कार्बन बढ़ रहा है, ब्लैक कार्बन बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलने से हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में झीलें बन रही हैं। जो भूकंप की दृष्टि से खतरनाक साबित हो सकती हैं।उन्होंने स्थानीय लोगों को चीड़ के पेड़ का इस शर्त पर पातन करने की अनुमति देने की सिफारिश की कि इसके बदले बांझ के पेड़ लगाए जाएं। जहां पर बरगद, पीपल, नीम इत्यादि के पेड़ पनप सकते हैं वहां पर इन पेड़ों को लगाया जाए। इसी तरह से उन्होंने लैंटाना और गाजर घास के आतंक का जिक्र करते हुए कहा कि इसने स्थानीय घास व झाड़ियों की सभी दूसरी प्रजातियों को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि मखमली बुग्यालों में अब जंगली सूअर दिखने लगे हैं और बुग्यालों की खुदाई कर रहे हैं जिससे वहां पर जड़ी-बूटियों का अस्तित्व खतरे में है। साथ ही आने वाले समय में भूस्खलन को भी इसे बढ़ावा मिल सकता है। उन्होंने मैती आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि 1 वर्ष में बहुत सी शादियां होती है अगर सभी वर-वधु एक-एक पेड़ भी लगाएं व उसको बचाएं तो 1 वर्ष में ही बहुत से पेड़ों का रोपण हो जाएगा, जो हरियाली बढ़ाने में उपयोगी होगा। उन्होंने लोगों को भावनात्मक रूप से मैती आंदोलन से जुड़ने की अपील की।ख उत्तराखण्ड में पर्यटन की संभावना विषय पर कमांडर दीपक खंडूरी ने अपने संबोधन में उत्तराखण्ड में पर्यटन के विविध आयाम का प्रस्तुतीकरण देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में ग्रामीण पर्यटन, पारिस्थितिकी पर्यटन, झील पर्यटन, वैलनेस पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, एंग्लिंग पर्यटन, वन्य जीव पर्यटन जैसे अनेक पर्यटन आयाम तेजी से विकसित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में अधिकतर पर्यटक नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, राजाजी पार्क में ही केंद्रित हो रहा है जिससे इन क्षेत्रों की कैरिंग कैपेसिटी ओवरलोड हो रही है। इससे यातायात, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो रहा है। उन्होंने इसके लिए पर्यटन के विविधीकरण पर काम करने की आवश्यकता बताई। कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार के अथक प्रयासों से उत्तराखण्ड में इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। रोपवे, सड़क, हवाई और रेल कनेक्टिविटी का तेजी से और गुणवत्तापूर्ण तरीके से विस्तार किया जा रहा है। उत्तराखण्ड के चारों ओर अनेक पर्यटक स्थल चयनित किए गए हैं और विकसित किया जा रहे हैं। पर्यटन के उत्थान और प्रबंधन के लिए अनेक मास्टर प्लान और सर्किट पर कार्य चल रहा है। जिससे उत्तराखण्ड पर्यटन के दृष्टिगत भी नंबर वन राज्य बनेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ संबोधन अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद ले. (रि.) जनरल बी. के. चतुर्वेदी और समापन संबोधन कर्नल (रि.) अजय कोठियाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष एस. एस. नेगी, सैनिक अधिकारी सी. के. अहलूवालिया, प्रदीप जोशी, कर्नल त्यागी सहित बड़ी संख्या में सेवानिवृत्ति सैनिक अधिकारी, स्कूली छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

सीएम ने किया 188.90 करोड़ की विकास योजनाओं तथा आपदा प्रबंधन कार्यों की स्वीकृतियों का अनुमोदन

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की महत्वपूर्ण विकास योजनाओं तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों के लिए रू. 188.90 करोड़ की लागत की स्वीकृतियां प्रदान की हैं।मुख्यमंत्री द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के अर्न्तगत गर्जिया (घुघुतीधार)-बेतालघाट-खैरना-ओड़ाखान-भटेलिया-मुक्तेश्वर मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-62) के कि.मी. 1 से 30 तक मार्ग के पुनर्निर्माण कार्य हेतु रू. 997.61 लाख, जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर में नवाबगढ़ पुल नं.-1 से खादर तक मोटर मार्ग का पुन: निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किए जाने हेतु रू. 312.55 लाख की योजना के साथ ही कुम्भ मेला-2027 के अन्तर्गत हरिद्वार में हरकीपैड़ी से ललतारो सेतु तक गलियों का सुधारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु रू. 925.94 लाख की योजना स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।मुख्यमंत्री श्री धामी के द्वारा जनपद उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगला-किच्छा मोटर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-44) के कि.मी. 12.6 से और कि.मी. 15 से 17.942 तक के हिस्से को दो लेन से चार लेन में बदलने की योजना के लिए रू. 8063.13 लाख की लागत की योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।मुख्यमंत्री द्वारा नगर निगम रूद्रपुर के अंतर्गत स्मार्ट वेंडिंग जोन के निर्माण कार्य हेतु रू. 255 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत एसएचपीसी द्वारा संस्तुत 07 नगर निकायों में कार्यों हेतु रू. 408.94 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने और शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत 11 नगर निकायों में पार्कों के सौंदर्यीकरण हेतु रू. 597.10 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से विभिन्न जनपदों को रू. 73.30 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके तहत जनपद चमोली को पुर्नप्राप्ति एवं पुनर्निर्माण मद में 5 करोड़ और राहत एवं बचाव मद में रू. 3 करोड़ की धनराशि दी गई है। इसी तरह जनपद नैनीताल को पुर्नप्राप्ति एवं पुनर्निर्माण मद में रू. 25 करोड़ के साथ ही जनपद उत्तरकाशी को पुर्नप्राप्ति एवं पुनर्निर्माण मद में रू. 30 करोड़ और राहत एवं बचाव मद में रू. 8 करोड़ की धनराशि दी गई है। जनपद चंपावत के लिए भी राहत एवं बचाव मद में रू. 2.30 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है।

स्वर्गीय दिवाकर भट्ट के परिजनों से मिले सीएम धामी

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी स्वर्गीय दिवाकर भट्ट के शिवलोक हरिद्वार स्थित आवास पर जाकर स्वर्गीय श्री भट्ट के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिवंगत श्री भट्ट के पुत्र ललित भट्ट सहित शोकाकुल परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना व्यक्त की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्री दिवाकर भट्ट ने आजीवन उत्तराखंड के सम्मान, अधिकारों और समग्र विकास के लिए काम किया। अग्रणी राज्यांदोलनकारी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी का योगदान सदैव याद रखा जाएगा।

श्रमिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और आधुनिक श्रम शासन की दिशा में हुआ ऐतिहासिक सुधार : शुभ्रा

नई श्रम संहिताएँ सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और पारदर्शी कम्प्लायंस का करेगी मजबूत ढांचा प्रदान

देहरादून। उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) शुभ्रा गोयल ने कहा कि भारत सरकार द्वारा पारित चार नई श्रम संहिताएँ वेतन संहिता, 2019 औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-परिस्थिति संहिता, 2020 स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश की श्रम व्यवस्था में किए गए सबसे व्यापक और दूरगामी सुधार हैं। इनका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करते हुए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, सामाजिक सुरक्षा को सार्वभौमिक बनाना और नियोक्ताओं के लिए बवउचसपंदबमे को सरल एवं पारदर्शी बनाना है।शुभ्रा गोयल ने बताया कि वेतन संहिता, 2019 का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब न्यूनतम वेतन का अधिकार सभी क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों तक पहुंच गया है। पुराने कानूनों में न्यूनतम वेतन केवल 'नियोजित व्यवसायों' तक सीमित था, जिससे लगभग 30 प्रतिशत श्रमिक ही लाभ ले पाते थे। नई संहिता के लागू होने से संगठित हो या असंगठित, सभी श्रमिक अब न्यूनतम वेतन के दायरे में आ गए हैं। इसके अलावा पहली बार 'फ्लोर वेज' का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत कोई भी राज्य केंद्र द्वारा निर्धारित बेसिक फ्लोर वेज से कम वेतन तय नहीं कर सकेगा। इससे देश भर में वेतन प्रणाली में समानता और न्याय सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि नई संहिताएँ 'इंस्पेक्टर राज' की अवधारणा को समाप्त कर पारदर्शी, तकनीक-आधारित निरीक्षण व्यवस्था लागू करती हैं। अब निरीक्षण वेब-बेस्ड और रैंडमाइज्ड होंगे, जिससे मानवीय हस्तक्षेप घटेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही 'इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर' की नई भूमिका के तहत अधिकारी केवल प्रवर्तन ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं को मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता भी प्रदान करेंगे। विवादों के त्वरित निपटारे के लिए दो-सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है जहां पक्षकार 90 दिनों में सुलह असफल होने पर सीधे अपील कर सकते हैं। औद्योगिक संबंध संहिता के तहत फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को वैधानिक मान्यता दी गई है। इसके लागू होने से FTE कर्मियों को स्थायी कर्मचारियों के समान सभी लाभ मिलेंगे। विशेष तौर पर ग्रेच्युटी के लिए अब एक वर्ष की सेवा पर्याप्त मानी जाएगी, जबकि पहले यह अवधि पांच वर्ष थी। इससे रोजगार में लचीलापन बढ़ेगा और उद्योगों को

आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने में आसानी होगी। गोयल ने बताया कि श्रमिकों की परिभाषा का क्षेत्र भी व्यापक किया गया है। अब सेल्स प्रमोशन कर्मचारी, वर्किंग जर्नलिस्ट तथा 18 हजार रुपये तक कमाने वाले सुपरवाइजरी कर्मचारी भी 'वर्कर' की परिभाषा में शामिल होंगे। इसी प्रकार 'इंडस्ट्री' की परिभाषा को भी विस्तारित कर गैर-लाभकारी एवं कम पूंजी वाली संस्थाओं को शामिल किया गया है। इससे बड़ी संख्या में श्रमिकों को सुरक्षा और वैधानिक लाभ मिल सकेंगे।उन्होंने कहा कि पहली बार भारत ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी मान्यता प्रदान की है। ओला-उबर के ड्राइवर, स्विगी-जोमैटो, अमेजन-फ्लिपकार्ट के डिलीवरी पार्टनर और अर्बन कंपनी से जुड़े सेवा प्रदाता अब सामाजिक सुरक्षा लाभों के दायरे में आ गए हैं। इनके लिए एक अलग सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया गया है, जिसमें एग्रीगेटर कंपनियाँ अपने वार्षिक टर्नओवर का 1 से 2 प्रतिशत तक योगदान देंगी। इस फंड से गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा, वृद्धावस्था लाभ और अन्य कल्याणकारी योजनाएँ संचालित की जाएँगी। इनका लाभ पोर्टेबल होगा, यानी श्रमिक चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करें, उन्हें मिलने वाले लाभ उनके साथ जुड़े रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑडियो-विजुअल प्रोडक्शन में कार्यरत पत्रकारों और सिने कर्मियों को भी विस्तारित सुरक्षा प्रदान की गई है। अब नियोक्ताओं के लिए नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा और इन कर्मियों पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की दरें लागू होंगी। महिला श्रमिकों के संदर्भ में नई संहिताएँ विशेष रूप से प्रगतिशील साबित होंगी। महिलाओं को किसी भी प्रतिष्ठान में और किसी भी समय रात 7 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तककार्य करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते नियोक्ता आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें। इसमें सुरक्षित परिवहन, पर्याप्त रोशनी, सीसीटीवी निगरानी, कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और शिफ्ट के लिए महिला कर्मियों की सहमति अनिवार्य होगी। गर्भावस्था और स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। नियोक्ताओं के compliances को सरल बनाने के लिए पुराने कानूनों में मौजूद आठ रजिस्ट्रेशन, चार लाइसेंस और 31 अलग-अलग रिटर्न की जगह अब एकल रजिस्ट्रेशन, एकल लाइसेंस और एकल रिटर्न की व्यवस्था लागू की गई है। इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर और रिकॉर्ड से न केवल प्रक्रिया सरल बनेगी बल्कि लागत भी कम होगी। पहली बार किए गए दंडनीय अपराधों के लिए समझौते का प्रावधान है, जिससे मुकदमेबाजी घटेगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। व्यावसायिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव करते हुए राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मानक तैयार करेगा और राज्यों के लिए इनका पालन अनिवार्य होगा। शुभ्रा गोयल ने कहा कि नई श्रम संहिताएँ भारत के श्रम तंत्र को सरल, आधुनिक, पारदर्शी और श्रमिक-केंद्रित बनाने का ऐतिहासिक कदम हैं। इनसे न केवल श्रमिकों के अधिकार मजबूत होंगे बल्कि उद्योगों के लिए भी सुगम, स्थिर और व्यापार-अनुकूल वातावरण तैयार होगा।

सिख धर्म की प्राचीन धरोहरों के संगत को करवाये दर्शन

गदरपुर। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा केलाखेड़ा में 350 वें शहीदी समागम के दौरान गुरबाणी पाठ के उपरांत रागी भाई हरजोत सिंह जख्मी जालंधर वाले ,हजूरी रागी भाई कुलदीप सिंह द्वारा मनोहर कीर्तन करके शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई,श्री गुरु तेग बहादुर के अलावा शहीद किए गए भाई मती दास,भाई सती दास एवं भाई दयाला जी की शहादत को नमन करते हुए उनके जीवन पर भाई हरजिंदर सिंह ने प्रकाश डाला वहीं शहीद भाई मती दास जी के परिजनों को भी स्मृति चिन्ह एवं सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। जिनमे भाई मतिदास जी की आठवीं पीढ़ी के सरदार अजीत सिंह, नवमी पीढ़ी के भाई हरिंदर सिंह और दसवीं पीढ़ी के भाई जिगर जीत सिंह को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिरोपा भेंटकर

सम्मानित किया। इस अवसर पर भाई मती दास जी के परिजनों द्वारा संगत को सिख धर्म के प्राचीन मोर पंख से बने चंदोआ, हुकमनामें और छतर के दर्शन कराये, इस मौके पर कमेटी अध्यक्ष परमजीत सिंह, बलबीर सिंह,अनिल कालरा, नरेश सिंह, गुरबख्शीश सिंह, जगजीत सिंह,अजीत सिंह ,मनिंदर सिंह सहित तमाम संगत मौजूद रही।

मांग पूरी होने पर शक्ति फार्म में मंत्री बहुगुणा का होगा जोरदार स्वागत

शक्तिफार्म। कई वर्षों से लंबित पड़ी चिकित्सा सुविधा की मांग को पूरा करने पर कल क्षेत्रीय विधायक व मंत्री सौरभ बहुगुणा का शक्ति फार्म में क्षेत्र वासियों द्वारा जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया जाएगा यहां बता दें कि क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शक्ति फार्म क्षेत्र वासियों की एक बड़ी समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण करते हुए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मंजरी दिला दी मंत्री सौरभ बहुगुणा के इस कदम को शक्ति फार्म क्षेत्र वासियों के लिए बड़ा और मजबूत कदम बताया जा रहा है। बताते चलें की यह समस्या शक्ति फार्म क्षेत्र वासियों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई थी। जानकारी मिली है कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधीक्षक सहित नौ अन्य 9 चिकित्सकों के साथ साथ 26 चिकित्सा स्टाफ की तैनाती की जाएगी व्हाट्सएप पुरानी इस समस्या का समाधान होने पर शक्ति फार्म क्षेत्र वासियों ने कल रविवार को शक्ति फार्म के टैगोर नगर के प्रांगण में कल जोरदार नागरिक अभिनंदन समारोह रखा है जिसमें मंत्री सौरभ बहुगुणा के साथ-साथ उनके पिता व उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी शामिल होंगे।

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय मामले में सतर्कता विभाग से खुली जांच के आदेश

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारों के दुरुपयोग के मामले में सख्त कदम उठाते हुए उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से संबंधित मामले की सतर्कता विभाग से खुली जांच कराए जाने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में पत्रावली पर भी अनुमोदन प्रदान कर दिया हैं।उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में विगत वर्षों में रू. 13.10 करोड़ के भुगतान में प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारों के दुरुपयोग होने का मामला सामने आया था। शासन के द्वारा इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच कराये जाने का निश्चय किया गया था। इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अनुमोदन प्रदान कर सतर्कता विभाग से खुली जांच कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

पंचतत्व में विलीन हुये वरिष्ठ पत्रकार निझावन

काशीपुर। सांध्य दैनिक 'दशानन' के सम्पादक अनिरुद्ध निझावन का बीते दिवस आकस्मिक निधन हो गया। आज गंगे बाबा रोड स्थित शमशान घाट पर उनके बड़े पुत्र ने उन्हें मुखाग्नि दी। बता दें अलीगंज रोड स्थित फसियापुरा निवासी अनिरूद्ध निझावन लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। बीते दिवस की दोपहर अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। आज सुबह उनके बड़े पुत्र सिद्धार्थ निझावन ने उन्हें मुखाग्नि दी। श्री निझावन के निधन के बाद से उन्हें निवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ लगी थी। वहीं आज सुबह उनके निवास समेत शमशान घाट पर भारी संख्या में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सामाजिक, राजनैतिक समेत पत्रकार जगत से जुड़े काशीपुर समेत रामनगर व जसपुर के तमाम पत्रकार मौजूद रहे। श्री निझावन अपने पीछे दो पुत्र, तीन पौत्र समेत तीन बेटियों व पत्नी से भरापूरा परिवार छोड़ गये हैं।

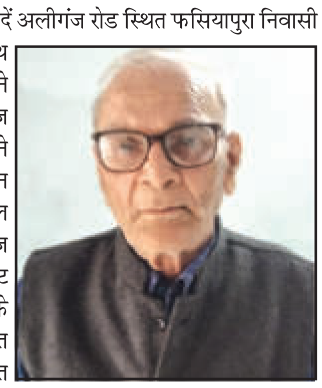

मेडिकल चौकी के पास युवक का शव मिला

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। बरेली रोड पर आज तड़के संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पाए जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां पर मौजूद लोगों से आवश्यक जानकारी लेकर शव कब्जे में लिया और पोस्ट मार्टम हाउस भिजवाया। समाचार लिखे जाने तक मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पुलिस ने आसपास के थाना क्षेत्रों में इसकी सूचना दे दी है। जानकारी के अनुसार आज तड़के करीब 4 बजे टहलने निकले लोगों ने मेडिकल चौकी से आगे सड़क किनारे एक युवक को अचेत अवस्था में पड़ा देखा। उन्होंने इसकी सूचना तत्काल एंबुलेंस और पुलिस को दी। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि युवक की उम्र लगभग 30 वर्ष है और उसके पहनावे से वह किसी संपन्न परिवार से प्रतीत हो रहा है। प्रारंभिक जांच में शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले, जिससे मौत रहस्यमयी बन हुई है।

विवाह के मण्डप से बाईक चोरी

काशीपुर। अज्ञात चोर एक विवाह मण्डप से बाईक चोरी कर ले गये। पुलिस ने वाईक स्वामी की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मौहल्ला महेशपुरा निवासी नरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र कैलाश सिंह ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बीती 26 नवंबर को अपनी हीरो होण्डा स्पलैण्डर प्लस संख्या यूए06एच 0719 कवि नगर स्थित कलश मण्डप के अन्दर खड़ी की थी जिसे अज्ञात चार चोरी कर ले गये। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की है।

जर्जर सड़क से बढ़ी मुसीबत, महिला को डोली से ले जाना पड़ा अस्पताल

सल्ट। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा क्षेत्र में लोगों को खराब सड़कों की वजह से फिर भारी परेशानी उठानी पड़ी,विधायक निधि से निर्मित थाकुली मैदारी मोटर मार्ग पिछले तीन साल से पूरी तरह क्षतिग्रस्त पड़ा है, गांव की एक महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन गांव तक सड़क टूटी होने के कारण कोई भी वाहन अंदर नहीं पहुंच पाया, कम मजबूर होकर ग्रामीणों ने

महिला को डोली पर बैठाकर कई किलोमीटर पैदल रास्ता तय किया और मुख्य सड़क तक पहुंचाया, जहां से उसे अस्पताल ले जाया गया।ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क तीन साल पहले विधायक निधि से बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद न तो कोई रखरखाव हुआ और न ही समय-समय पर सफाई। बरसात के बाद से सड़क की हालत और बिगड़ चुकी है। कई जगह गहरी खाई बन गई है और वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं है।स्थानीय लोग बताते हैं कि समस्या की जानकारी विभाग और जनप्रतिनिधियों को कई बार दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़क की मरम्मत जल्द नहीं हुई, तो आपात स्थिति में किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका है।इस मुद्दे पर सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि यह सड़क वास्तव में विधायक निधि से बनाई गई थी, उन्होंने कहा कि बरसात में काफी रोडें क्षतिग्रस्त हुई है, और पहाड़ों की भौगोलिक स्थिति अलग है उन्होंने कहा कि इसका सर्वे लोक निर्माण विभाग द्वारा कर लिया गया है और जल्दी ही इस रोड को बना लिया जाएगा.ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सुधार कार्य नहीं हुआ, तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मरम्मत और सफाई न होने से सड़क गड्ढों, मलबे और धंसान से भरी है, जिसका खामियाजा आम लोगों को हर दिन भुगतना पड़ रहा है। शुक्रवार को को सड़क की खराब स्थिति ने ग्रामीणों की मुश्किलें और बढ़ा दीं।शुक्रवार सुबह

मांस प्रकरण में रामनगर कोर्ट से मिली तीन आरोपियों को जमानत

रामनगर। बीती 23 अक्टूबर को रामनगर के ग्राम छोई क्षेत्र में हुए चर्चित मांस प्रकरण के मामले में रामनगर में स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से इस प्रकरण में जेल में बंद तीन आरोपियों की जमानत मंजूर हो गई है मामले में जमानत मंजूर होने के बाद आरोपियों के परिजनों में खुशी का माहौल है इस मामले में रामनगर के वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक जोशी ने बताया कि उक्त मांस के प्रकरण मामले में नूरजहां ने पुलिस को दी तहरी में बताया था कि उसके पति नासिर बरेली से पिकअप वाहन में भैंस का मांस ला रहे थे तभी छोई के पास कुछ लोगों द्वारा उनके पति के साथ मारपीट करते हुए जानलेवा हमला किया गया था उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 109 एवं 190 के अलावा कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था इस मामले में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन जोशी को मुख्य आरोपी बनाया गया था जो कि वर्तमान में जेल में बंद है अधिवक्ता दीपक जोशी ने बताया कि उनके द्वारा इस मामले में जेल में बंद करन उर्फ कपिल बिष्ट, विकास उर्फ विकास, श्याम सिंह उर्फ संजू का जमानत पत्र उनके द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में प्रस्तुत किया गया था उन्होंने बताया कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा इस मामले की सुनवाई करते हुए उक्त तीनों आरोपियों की जमानत आज मंजूर कर दी गई है उन्होंने बताया कि जमानत के तौर पर एक एक लाख रुपए के जमानती कोर्ट में पेश करने होंगे तो वही आपको बता दें कि इस प्रकरण में तीन आरोपियों की जमानत मंजूर होने के बाद भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन जोशी एवं अन्य लोगों की जमानत की राह भी अब आसान हो गई है हालांकि इस मामले में कुछ आरोपियों द्वारा अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में जमानत पत्र दाखिल किया गया था लेकिन उच्च न्यायालय ने इन्हें खारिज कर दिया था अधिवक्ता दीपक जोशी ने बताया कि अन्य आरोपियों की जमानत भी पेरिटी बेस पर न्यायालय से मिल सकती है।

कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहली बार दिखी यूरोप-एशिया की दुर्लभ 'हॉफिंच' चिड़िया

रामनगर। विश्वप्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क ने एक बार फिर अपनी जैव विविधता से दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। यहां पहली बार यूरोप, पूर्वी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में पाई जाने वाली दुर्लभ पक्षी प्रजाति हॉफिंच देखी गई है, इस अद्भुत दिखने वाले प्रवासी पक्षी के अचानक कॉर्बेट में नजर आने से वनाधिकारी और पक्षी प्रेमी बेहद उत्साहित हैं,विशेषज्ञों का अनुमान है कि झुंड में रहने वाला यह पक्षी संभवत: अपने दल से बिछड़कर यहां पहुंच गया होगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने हॉफिंच की मौजूदगी की पुष्टि करते हुए इसे पार्क में पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियों की आधिकारिक सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है,यह पहली बार है जब इस पक्षी को देश के किसी भी नेशनल पार्क में देखा गया है, जिससे यह साइटिंग बेहद खास बन गई है। 23 नवंबर को रामनगर के जाने-माने फोटोग्राफर प्रशांत कुमार ने ढेला जोन में जंगल सफारी के दौरान शिकारी कुएं के पास इस पक्षी को कैमरे में कैद किया। प्रशांत बताते हैं कि भारत में हॉफिंच का दिखना ऐतिहासिक है,यह प्रजाति सामान्यत: बेहद ठंडे इलाकों में पाई जाती है और यूरोप, उत्तरी तथा पश्चिमी एशिया में इसका निवास क्षेत्र माना जाता है। उन्होंने बताया कि यह पक्षी इन दिनों ढेला रेंज में लगातार नजर आ रहा है, जिससे अनुमान है कि यह अपने झुंड से बिछड़कर यहां तक पहुंचा होगा. प्रशांत के अनुसार, इससे पूर्व

हॉफिंच केवल दो बार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (च्व्ज्ञ) में दिखाई दी थीएक बार 1908 में मुजफ्फराबाद में और दूसरी बार वर्ष 2017 में अलियाबाद में। इसके बाद अब कॉर्बेट में दिखना इस प्रजाति की तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण साइटिंग मानी जा रही है। हॉफिंच एक मजबूत और आकर्षक चिड़िया है,लंबाई: लगभग 18 सेंटीमीटर,पंख फैलाव: 29 से 33 सेंटीमीटर,भोजन: मुख्य रूप से कठोर बीज और जामुन,रंग: नर और मादा के पंखों में हल्का अंतर, जिसमें नर का रंग अधिक चमकीला होता है। इसका व्यवहार झुंड में रहना और कठोर बीजों को तोड़ने की क्षमता इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है।प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवार बताते हैं कि हॉफिंच सामान्यत: पूरे यूरोप और समशीतोष्ण एशिया में प्रजनन करती है,कुछ एशियाई समूह सर्दियों में दक्षिण की ओर पलायन करते हैं। अलास्का के पश्चिमी द्वीपों में यह दुर्लभ वागाबॉन्ड (भटकने वाली) प्रजाति मानी जाती है।वहीं सीटीआर के एसडीओ अमित ग्वासाकोटी ने बताया कि कॉर्बेट में पहली बार हॉफिंच का दिखना पक्षी प्रेमियों के लिए उत्साहजनक है,जल्द ही इसे पार्क की बर्ड स्पीशीज लिस्ट में शामिल किया जाएगा। कॉर्बेट में हॉफिंच की उपस्थिति न केवल जैव विविधता का प्रमाण है, बल्कि यह दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय प्रजातियां भी इस जंगल की समृद्ध पारिस्थितिकी से आकर्षित हो रही हैं।

हरिद्वार, पंतनगर एवं औली में स्थापित होंगे अत्याधुनिक मौसम पूर्वानुमान राडार

विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन व 20 वाँ राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2025 देहरादून में आयोजित विज्ञान, तकनीक, शोध और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाने पर दिया गया जोर

देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में देहरादून स्थित ग्राफिक एरा सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन एवं 20वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन2025 में बतौर विशिष्ट अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर एनडीएमए के सदस्य डॉ. दिनेश कुमार असवाल की पुस्तकों का विमोचन भी किया गया।कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाली प्रतिभाशाली महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यभर के विभिन्न शोध एवं शैक्षणिक संस्थानों से चयनित वैज्ञानिकों को Young Women Scientist Achievement Award–2025 UCOST Young Women Scientist Eñcellence Award प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान, अनुसंधान और तकनीक आधारित नवाचार आपदा प्रबंधन को सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उत्तराखंड की युवा महिला वैज्ञानिकों का शोध कार्य न केवल राज्य बल्कि देश और विश्व के लिए प्रेरणादायक है।सम्मानित वैज्ञानिकों में यंग वीमेन साइंटिस्ट अचीवमेंट अवार्ड 2025 (45 वर्ष तक) के अंतर्गत डॉ. अंकिता राजपूत, डॉ. गरिमा पुनेठा, डॉ. ममता आर्या, डॉ. हर्षित पंत, डॉ. प्रियंका शर्मा और डॉ. प्रियंका पांडे शामिल रहीं। वहीं यूकॉस्ट यंग वीमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड (30 वर्ष तक) के अंतर्गत डॉ. प्रियंका उनियाल, पलक कंसल, राधिका खन्ना, स्तुति आर्या तथा श्रीमती देवयानी मुंगल को सम्मानित किया गया।केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस विश्व आपदा सम्मेलन के आयोजन के लिए उत्तराखंड से बेहतर स्थान और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थानों के सहयोग से आयोजित यह सम्मेलन आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक दूरदर्शी और अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने घोषणा की कि हरिद्वार, पंतनगर और औली में अत्याधुनिक मौसम पूर्वानुमान राडार स्थापित किए जाएंगे, जो राज्य में मौसम संबंधी चेतावनी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाएंगे। डॉ. सिंह ने "सिलक्यारा विजय अभियान" का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अभियान ने सिद्ध किया कि दृढ़ इच्छाशक्ति, मजबूत नेतृत्व और वैज्ञानिक दक्षता किसी भी जटिल चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर सकती है।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि इस तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधि तथा देश-विदेश से आए वैज्ञानिक और शोध कर्ता हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों पर विस्तृत विचार-विमर्श करेंगे। साथ ही, तकनीकी नवाचार, अनुसंधान सहयोग तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में ठोस रणनीतियाँ बनाई जाएँगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस सम्मेलन से प्राप्त सुझाव और समाधान न केवल उत्तराखंड, बल्कि पूरे विश्व के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय केवल पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का जीवन स्रोत है। यहाँ की नदियाँ, ग्लेशियर और जैव विविधता पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से हिमालय का संतुलन प्रभावित हो रहा है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बदलते मौसम पैटर्न, बढ़ती वर्षा की तीव्रता, अप्रत्याशित क्लाउडबर्स्ट और भूस्खलन की घटनाओं ने नई चिंता उत्पन्न की है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं और क्षेत्र विशेषज्ञों के बीच बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इसी दिशा में यह विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन एक सेतु का कार्य करेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए 4P मंत्र Predict Prevent Prepare Protect के आधार पर 10 सूत्रीय एजेंडा लागू किया गया है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण सिल्क्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान देखने को मिला, जहां 17 दिनों के अथक प्रयासों से 41 श्रमिकों को सुरक्षित बचाया गया। यह अभियान आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ। उन्होंने कहा कि इस अभियान के बाद राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को राहत एवं बचाव तक सीमित न रखते हुए वैज्ञानिक तकनीकों, जोखिम आकलन, एआई आधारित चेतावनी प्रणाली और संस्थागत समन्वय को मजबूत करने की दिशा में ठोस पहल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण कार्यक्रम और जनभागीदारी के माध्यम से हिमालय के दीर्घकालिक संरक्षण के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि रैपिड रिस्पांस टीमें गठित करने, ड्रोन सर्विलांस, जीआईएस मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेंसर आधारित झील मॉनिटरिंग पर भी कार्य किया जा रहा है। साथ ही, अर्ली वार्निंग सिस्टम को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पौधरोपण, जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रमों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सौर ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग रिजुविनेशन अथॉरिटी का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत पारंपरिक जल स्रोतों का चिन्हीकरण और पुनर्जीवन कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू किया गया है, जिसके माध्यम से प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन में उल्लेखनीय सफलता मिली है और अब तक हिमालयी क्षेत्र में 72 टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। इसी प्रकार अपनाए गए नवाचारों का परिणाम है कि नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड को देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह सम्मेलन आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में विश्व को नई दिशा प्रदान करेगा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, सचिव श्री नितेश झा, यूकॉस्ट महानिदेशक श्री दुर्गेश पंत, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के चेयरमैन श्री कमल घनशाला, विभिन्न देशों के राजदूतगण, केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारीगण, देश-विदेश से आए शोधकर्ता, विषय विशेषज्ञ तथा ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य एवं छात्र उपस्थित रहे।

अरुणा प्रदेश प्रभारी, मंजू जिला व अर्चना अध्यक्ष मनोनीत

हल्द्वानी (उद संवाददाता)।अखिल एकता उद्योग व्यापार मण्डल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी अतुल कुमार गुप्ता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव जायसवाल, राष्ट्रीय महिला महासचिव तनुजा जोशी, राष्ट्रीय महिला सचिव सीमा देवल व उत्तराखंड प्रदेश महिला अध्यक्ष बीनू जायसवाल की संस्तुति से प्रदेश महिला विंग मे हल्द्वानी से तीन महिला उद्यमी व समाजसेवी को जिसमें प्रदेश महिला प्रभारी के पद पर अरुणा टंडन, महिला जिला अध्यक्ष पर मंजू दानू व महिला महानगर अध्यक्ष पर अर्चना मित्तल को मनोनीत किया। इस मनोनयन से हल्द्वानी की महिला उद्यमियों मे काफी हर्ष व्याप्त है। प्रदेश प्रभारी अतुल गुप्ता ने नवनियुक्त समाजसेवी अरुणा टंडन के आवास पर पहुंचकर नवनियुक्त महिला पदाधिकारी का संगठन का प्रमाण पत्र व संगठन के प्रेरणा सूत्र भामाशाह की चित्र

भेंट कर स्वागत किया। स्वागत के दौरान सभी पदाधिकारी बहनो का एक दूसरे के परिचय करते हुए संगठन मे महिला बहनो को सशक्त, आत्मनिर्भर एवं स्वरोजगार युक्त बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान राष्ट्रीय महिला महासचिव तनुजा जोशी, राष्ट्रीय महिला सचिव सीमा देवल, उत्तराखंड महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती बीनू जायसवाल, सदस्य कुसुम लता केसरवानी, जिलाध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

रात्रि में नहीं चलेंगे टैंपो और ई-रिक्शा

रुद्रपुर। उधमसिंहनगर में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने रात के समय टैंपो और ई-रिक्शा के संचालन पर रोक लगा दी है। आदेश के अनुसार अब रात्रि में बिना अनुमति कोई भी टैंपो या ई-रिक्शा सड़क पर नहीं चलेगा। यह निर्णय जन सुरक्षा, दुर्घटनाओं में कमी और रात्रिकालीन संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण के मद्देनजर लिया गया है।एसएसपी मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि किसी अत्यावश्यक स्थिति में चालक संबंधित क्षेत्राधिकारी (सीओ) से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही वाहन चला पाएंगे। बिना अनुमति रात्रि में प्रतिबंधित वाहनों का

संचालन करते पाए जाने पर संबंधित चालकों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।पूरे जनपद में रात्रि के दौरान सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सभी थाना व चौकी प्रभारियों तथा यातायात पुलिस को रात्रिकालीन चेकिंग में विशेष सतर्कता बरतने, प्रतिबंधित वाहनों सहित संदिग्ध व्यक्तियों और देर रात चल रहे अन्य वाहनों की गहन जांच सुनिश्चित करने को कहा गया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे जनहित में लिए गए इस निर्णय में पुलिस का सहयोग करें, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

सभासद सुशीला राय का बोर्ड बैठक से बहिष्कार

वार्ड 2 के विकास कार्यों को रोकने का लगाया आरोप

शक्तिफार्म। नगर के वार्ड 2 की सभासद सुशीला राय ने आरोप लगाया है कि बोर्ड गठन के बाद उन्होंने नगर पंचायत शक्तिगढ़ को 17 विकास कार्यों के प्रस्ताव दिए थे, जिन्हें सर्वसम्मति से पास भी किया गया था, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बावजूद इनमें से एक भी कार्य धरातल पर शुरू नहीं हो पाया है। सभासद सुशीला राय ने बताया कि जल निकासी की गंभीर समस्या से जूझ रहे वार्डवासियों के लिए नाली निर्माण तथा विभिन्न स्थानों पर मार्ग निर्माण कार्य अत्यंत आवश्यक थे, जिन्हें प्रस्ताव में प्रमुखता से शामिल किया गया था। लेकिन, उनके अनुसार योजनाबद्ध तरीके से वार्ड 2 के विकास कार्यों को रोका जा रहा है। सुशीला राय ने आरोप लगाया कि "मेरे वार्ड के विकास को जानबूझकर ठप्प किया जा रहा है। जनता के अधिकारों पर खुली राजनीति और भेदभाव हो रहा है।" इसी के विरोध में उन्होंने आज नगर पंचायत बोर्ड की बैठक का कड़ा बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि जो भी लोग वार्ड की जनता के अधिकारों पर चोट पहुँचाने का प्रयास करेंगे, उन्हें कड़ा जवाब दिया जाएगा। "विकास रुकेगा नहीं, लड़ाई और तेज होगी," सभासद सुशीला राय ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा। वार्ड 2 के स्थानीय लोग भी लगातार जलनिकासी व सड़क समस्याओं को लेकर नाराजगी जता रहे हैं और शीघ्र समाधान की मांग कर रहे हैं।

उत्तराखंड में हो रहा चहुंमुखी विकास: जोशी

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। भाजपा संभाग कार्यालय में भाजपा उत्तराखण्ड के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में चल रही राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे अभूतपूर्व विकास कार्यों व नीतिगत निर्णयो के विषय में प्रेसवार्ता की गई। श्री जोशी ने बताया कि डबल इंजन की सरकार के समन्वय से उत्तराखण्ड राज्य आज चौहुमुखी विकास के साथ राष्ट्रीय स्तर के सभी मानको में एक अग्रणी राज्य के रूप में आगे आ रहा है और राज्य के 25 वर्ष के कालखण्ड में यह समय राज्य का स्वर्णिम काल चल रहा है।उन्होने बताया विगत 5 दशको से बहुप्रतिक्षित जमरानी बांध परियोजना जिसे तराई भाबर की लाईप लाईन के तौर पर जाना जाता है आज घरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। इसके साथ की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जो कि धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है आज अपने अन्तिम चरण में है। इसके अतिरिक्त हल्द्वानी के बढ़ते हुए स्वरूप को देखते हुए रिंग रोड़ परियोजना भी शीघ्र प्रारम्भ होने जा रही है। पर्यटन के क्षेत्र में इस वर्ष चारधाम में विपरीत मौसम के बावजूद भी श्रद्धालुओं रिकार्ड 51 लाख की संख्या में आए। साथ ही कुमाऊँ में मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के तहत कैचीधाम, जागेश्वर धाम, बाराही धाम, गोल्ज्यू सर्किट, नंदादेवी मन्दिर, इत्यादि का समुचा आधारभूत विकास किया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हल्द्वानी व अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त रूद्रपुर व पिथौरागढ़ में भी मेडिकल कॉलेज निर्माण तीव्र गति से सुचारू है। शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय विद्यालयो में भी अटल उत्कृष्ट विधालयो के माध्यम से आम छात्रो को सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से अग्रेजी मीडियम में शिक्षा प्रदान की जा रही है। श्री जोशी ने पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड सीमान्त राज्य होने के कारण केन्द्र सरकार की वाईबरेन्ट विलेज योजना के तहत 51 गाँवो का मूलभूत विकास किया जा रहा है और साथ ही भारत माला प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सीमांत क्षेत्र की सड़को को 9 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। उन्होने बताया कि धामी सरकार द्वारा विगत 4 वर्षो में रिकार्ड 26 हजार लोगो को सरकारी नौकरियो में नियुक्त किया गया है। इन्वेस्टर मीट जिसमे कि धामी सरकार द्वारा 3 लाख 56 हजार करोड़ के एमओयू साईन किये गये थे जिसमे कि 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउड़िग की जा चुकी है। स्वरोजगार के क्षेत्र में वीर चन्द्र गढ़वाली योजना, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, बागवानी क्षेत्र में एपिल मिशन, ट्राउट फार्मिंग, महिलाओ के स्वय सहायता समूह द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। खनन के क्षेत्र में रिकार्ड राजस्व की बढ़ोतरी राज्य सरकार की उत्कृष्ट खनन नीति का समर्थन करती है। साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा राज्य की खनन नीति से. प्रभावित होकर राज्य को 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि निर्गत की है। आधारभूत क्षेत्र में भूतल परिवाहन में पीएमजीएसवाई व एनएच द्वारा राज्य के सुदूर क्षेत्रो को रोड़ो के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। केन्द्र सरकार की उड़ान योजना के तहत पिथौरागढ़, धारचूला व मुनस्यारी जैसे दूरस्थ क्षेत्र आज कुछ ही मिनटो में हल्द्वानी व देहरादून से सम्पर्क में है।धामी सरकार की सख्त भ्रष्टाचार निरोधक नीति के तहत आज 200 से ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी जेल के सलाखो के पीछे है। राज्य की डेमोग्राफी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद गंभीर है और इसी के तहत लेण्ड जिहाद व विगत वर्षों में वर्ग विशेष द्वारा बनाए गए स्थाई निवास व अन्य आईडी पूफ्रो की गहन जाच का अभियान पूरे प्रदेश में गतिमान है। सुरेश जोशी ने बताया कि यह सब योजनाए वह उपलब्धिया उत्तराखण्ड की डबल इंजन सरकार की उत्तराखण्ड राज्य को विकसीत आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाती है और भारत के 2047 विकसित भारत बनने की दिशा में उत्तराखण्ड राज्य मुख्यमंत्री श्री धामी के नेतृत्व में निरन्तर क्रियाशील व संकल्पित है। इसी के परिणाम स्वरूप नीति आयोग के अन्तर्गत वर्ष राज्यो की सतत् विकास लक्ष्य रैकिंग में उत्तराखण्ड राज्य ने सम्पूर्ण देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रेसवार्ता से पूर्व संभाग कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा उत्तराखण्ड के मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी का पुष्पगुच्छ व पटका पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट, प्रदेश सह-मीडिया प्रभारी प्रदीप जनौटी, जिला महामंत्री विनीत अग्रवाल, जिला मीडिया प्रभारी नितिन राणा, जिला मंत्री प्रताप रैक्वाल, जिला सह सोशल मीडिया प्रभारी रत्नेश साह, मण्डल अध्यक्ष हल्द्वानी मधुकर श्रोत्रिय व मण्डल अध्यक्ष मुखानी दलीप नेगी उपस्थित रहे।

मीरी पीरी खालसा अकैडमी में चलाया वृहद् वृक्षारोपण एवं सफाई अभियान

गदरपुर । पर्यावरण संरक्षण हेतु वृहद् वृक्षारोपण करते हुए सफाई अभियान चलाकर गुरुद्वारा श्री गुरु हरगोबिंदसर नवाबगंज के मुख्य सेवादार बाबा अनूप सिंह के नेतृत्व में सेवादारों द्वारा सहयोग किया गया । गुरुद्वारा श्री गुरु हरगोबिंदसर नवाबगंज उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के मुख्य सेवादार वीर अनूप सिंह द्वारा बताया गया कि गुरबाणी के अनुसार हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य हमारे जीवन के लिएष्पवन गुरु पानी पिता माता धरति महत ष्हवा, पानी एवं धरती के संरक्षण के लिए के सभी को कर्तव्य निभाना चाहिए उनके द्वारा गुरुद्वारा साहिब एवं मीरी पीरी खालसा अकैडमी के मुख्य मार्ग पर विभिन्न प्रकार के छायादार, फलदार एवं औषधीय पौधों का रोपण कार्य किया जा रहा है । उन्होंने बताया कि इस मार्ग के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी सेवादारों एवं अकादमी के स्टाफ एवं बच्चों के सहयोग से पेड़ पौधों का रोपण करने के साथ उनका संरक्षण करने का भी आह्वान किया जा रहा है, उन्होंने कहा, मानवता के लिए जो प्रदूषण खतरनाक होता है उससे निजात पाने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाकर सभी को इस अभियान में शामिल होना चाहिए ।

सहकारी समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित संचालक मंडलो ने ली शपथ

गदरपुर। बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड गदरपुर में बृहस्पतिवार को समिति के एसडीओ एवं एम डी कोशल गिरी द्वारा शपथ समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष पूजा दत्त, उपाध्यक्ष फरहा मोहम्मद शादाब को संचालक मंडल के साथ अपने दायित्वों का ईमानदारी,पारदर्शिता और समर्पण के साथ निर्वहन करने की शपथ दिलाई वहीं मौजूद किसानों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारी का फूल मालाओ से स्वागत किया । वही नवनिर्वाचित अध्यक्ष पूजा दत्त ने कहा कि सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था

की रीड है और सरकार किसानों की प्रगति के लिए लगातार कार्य कर रही है । वही फरहा मोहम्मद शादाब ने विश्वास दिलाया कि वे किसानों के हितों को सर्वोपरि रखकर कार्य करेंगे । उनकी टीम के आने से समिति में नई ऊर्जा का संचार हुआ है ।किसानों को सभी सुविधाएं पारदर्शी व समय पर उपलब्ध कराना प्राथमिक लक्ष्य रहेगा। वही सरकारी समिति गदरपुर की टीम ने संचालक मंडल सहित रईस अहमद, अध्यक्ष प्रतिनिधि अमरीक सिंह, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि मोहम्मद शादाब, सरफराज, मोहम्मद फारूक के अलावा अन्य कई किसानों को भी सम्मानित किया।

स्थानांतरण पर सीओ नितिन लोहनी को दी विदाई

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। नितिन लोहनी का सीबीसीआईडी सैक्टर हल्द्वानी स्थानान्तरण होने पर जनपद पुलिस द्वारा एक विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। एसएसपी डॉ0 मंजुनाथ टीसी द्वारा क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी नितिन लोहनी का सीबीसीआईडी सैक्टर हल्द्वानी में स्थानान्तरण होने पर भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह के दौरान उनके कार्य के प्रति समर्पण तथा बेहतर कार्य कुशलता की प्रशंसा करते हुए अग्रिम तैनाती की शुभकामनाएं दी गई। सीओ नितिन लोहनी वर्ष 2021 से जनपद में नियुक्ति के दौरान क्षेत्राधिकारी रामनगर, क्षेत्राधिकारी भवाली, क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन, तथा इसके उपरांत क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी के पद पर तैनात रहे। उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण मामलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। विदाई समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ0 जगदीश चन्द्रा, क्षेत्राधिकारी रामनगर सुमित पांडे क्षेत्राधिकारी नैनीताल अमित कुमार तथा प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाईन नैनीताल हरकेश सिंह मौजूद रहे।

पंडित राम सुमेर शुक्ल की जयंती पर स्वास्थ्य व रक्तदान शिविर आयोजित

ग्राम नजीमाबाद गुरुद्वारा सिंह सभा (जीरो बंधा) में सुखमणि साहिब पाठ, लंगर का आयोजन

किच्छा।तराई के संस्थापक, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं जनसेवा के प्रतीक स्वर्गीय पंडित राम सुमेर शुक्ल जी की 110वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज ग्राम नजीमाबाद गुरुद्वारा सिंह सभा जीरो बंधा में समाजसेवियों तथा स्थानीय नागरिकों द्वारा भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुद्वारा साहिब में सुखमणि साहिब के पावन पाठ से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर उनकी स्मृति को नमन किया। पाठ पश्चात संगत को लंगर का प्रसाद वितरित किया गया, जिसमें महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। गुरुद्वारा परिसर में कात्यायनी अस्पताल, रुद्रपुर के सहयोग से विशाल नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर और चौरिटेबल ब्लड बैंक रुद्रपुर के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दोनों शिविरों का विधिवत शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख रीना गौतम तथा पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। शिविर में कात्यायनी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम द्वारा रक्तचाप, मधुमेह, नेत्र रोग, महिला स्वास्थ्य, सामान्य जांच सहित अनेक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की गईं। बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। वहीं रक्तदान शिविर में 42 युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए रक्तदान किया।अपने संबोधन में ब्लॉक प्रमुख रीना गौतम ने कहा कि स्वर्गीय पंडित राम सुमेर शुक्ल जी ने जिस दूरदर्शिता और त्याग से तराई के बसावट कार्य को सफल बनाया, वह सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। उनके जन्मदिन पर आयोजित यह शिविर समाज सेवा की उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि तराई के विकास की मजबूत नींव पंडित राम सुमेर शुक्ल जी के प्रयासों से रखी गई थी। आज हजारों परिवार जिस सुरक्षित और विकसित तराई में रह रहे हैं, उसका श्रेय उनके अथक परिश्रम और राष्ट्रहित में किए गए योगदान को जाता है। ग्रामीण मंडल अध्यक्ष मयंक तिवारी, गोल्डी गोराया, बंटी खुराना, हरविंदर सिंह चुग, श्रेयांश शुक्ला, आशीष शुक्ला, ग्राम प्रधान राहुल कुमार, सावन सिंह, शेर सिंह, अजय साहनी, बलविंदर सिंह, मनमोहन सक्सेना, धर्मराज जायसवाल, संदीप अरोड़ा, अजय सिंह, तेजविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, निशान सिंह, कुलविंदर सिंह, गोविंद सिंह, सवन सिंह, राम सिंह, छिंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, लखविंदर सिंह, मोहन सिंह, बलवीर सिंह, बॉबी सिंह, करणवीर सिंह, मनजीत सिंह, हरविंदर सिंह, धीरज सिंह, दीपक मिश्रा, रजनीश कुमार, सरोज चौहान, गुरुमुख सिंह, महेंद्र सिंह, नितिन वाल्मीकि, विनोद कोली, सचिन सिंह, नारायण सिंह समेत गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, कात्यायनी अस्पताल के चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी, समाजसेवी, स्थानीय नागरिक, महिला मंडल, युवा संगठन और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

उत्तरांचल दर्पण
सम्पादकीय सत्यम् शिवम् सुन्दरम्

सोशल मीडिया पर अंकुश

पिछले कुछ समय से इंटरनेट की असीमित दुनिया में पसरी वैसी सामग्री को लेकर एक व्यापक चिंता पैदा हुई है, जो बच्चों और किशोरों के व्यक्तित्व पर नकारात्मक असर डालती है, उनके सोचने-समझने की दिशा को बुरी तरह प्रभावित करती है। इसके मद्देनजर दुनिया के कई देशों ने अपने स्तर पर ऐसे नियम-कायदे भी बनाए हैं, जिनके जरिए सोशल मीडिया और इस तरह के अन्य इंटरनेट मंचों तक बच्चों और किशोरों की पहुंच को सीमित किया गया। भारत में भी इस मसले पर चिंता के स्वर उभरे हैं कि व्यापक उपयोगिता के समांतर इंटरनेट की निर्बाध दुनिया में मौजूद आपत्तिजनक सामग्री को लेकर एक ठोस नियमन हो, ताकि नाबालिगों को उसके नकारात्मक असर से बचाया जा सके।इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति अपने सोशल मीडिया खाते या वीडियो चैनल पर किसी तरह की आपत्तिजनक सामग्री तैयार करके जारी करता है, तो उसे रोकने को लेकर नियम-कायदे की भी कमी है। यही वजह है कि किशोरों या नाबालिगों सहित इंटरनेट की सुविधा रखने वाला हर व्यक्ति अलग-अलग मंचों पर उपलब्ध अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री तक भी आसान पहुंच रखता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि इस संबंध में एक स्वायत्त नियामक संस्था के गठन की जरूरत है, जो इस पर लगाम लगा सके। एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सुझाव के तौर पर यह भी कहा कि इंटरनेट पर उपलब्ध अश्लील या वयस्क प्रकृति की सामग्री को बच्चों से दूर रखने के लिए आधार नंबर से उम्र की पुष्टि करने पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें कोई दोराय नहीं कि नई तकनीक और प्रौद्योगिकी के तेजी से विस्तार के दौर में आसपास की दुनिया और व्यवस्थागत ढांचे में भी व्यापक बदलाव आ रहे हैं। रोजगार से लेकर पढ़ाई-लिखाई और मनोरंजन जैसी जरूरतों के लिए इंटरनेट पर निर्भरता का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा है। मुश्किल यह है कि जिस साइबर संसार ने जीवन को आसान बनाया है और अध्ययन तथा शोध से संबंधित मामलों में अपनी उपयोगिता साबित की है, उसी में ऐसी सामग्री का असीमित भंडार भी है, जिसे समाज के लिए नुकसानदेह माना जाता है। ओटीटी मंचों, यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भरे पड़े हैं, जिन्हें आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री की श्रेणी में रखा जा सकता है और जो बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं। आस्ट्रेलिया और डेनमार्क जैसे देशों ने सोशल मीडिया तक अपने यहां के नाबालिगों की पहुंच को सीमित करने के लिए नियम-कायदे बनाए हैं, तो इसके पीछे यही चिंता है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की यह राय गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर उम्र की जांच के लिए आधार नंबर का उपयोग किया जा सकता है। मगर एक पहलू यह भी है कि आधार नंबर की संवेदनशीलता और उसके जोखिम के मद्देनजर उसे सभी जगहों पर न देने की सलाह दी जाती है। ऐसे में अगर साइबर संसार का कोई मंच उम्र की पुष्टि के लिए किसी व्यक्ति का आधार और उससे जुड़े ब्योरे लेता है, तो यह कैसे सुनिश्चित होगा कि उसका किसी भी तरह से दुरुपयोग न हो। जाहिर है, इंटरनेट की व्यापक दुनिया के कुछ नुकसानों को देखते हुए नियमन के लिए एक ढांचा खड़ा करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत होगी कि इसके नाम पर लोकतंत्र तथा अभिव्यक्ति के अधिकार को चोट न पहुंचे और वह लोगों की स्वस्थ, आलोचनात्मक और जनतांत्रिक चेतना को बाधित न करे।

आक्रामक साजिशों के बीच संविधान की असल ताकत

26 नवम्बर आज केवल एक तारीख नहीं, आज की तारीख देश की आत्मा, उसके बुनियादी ढांचे और जनता की सर्वोच्चता की याद दिलाने वाला दिन है। संसद के गौरवशाली भवन में जब राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और विभिन्न दलों के नेता संविधान दिवस पर अपने विचार रखते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जानते हैं कि असली नैतिक शक्ति उस मोटी किताब में दर्ज जनता के अधिकारों से आती है। इसी वजह से आज की राजनीति में संविधान दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि विचारधाराओं की टकराहट, जनता के समर्थन की होड़ और भविष्य के भारत की दिशा तय करने का अहम मौका बन चुका है। सवाल यह उठता है कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो फिर संविधान दिवस 26 नवम्बर को क्यों मनाया जाता है। इसका उत्तर इतिहास के उस निर्णायक क्षण में छुपा है जब 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने बहस, मतभेद और भारी मंथन के बाद भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था। कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की लगातार मेहनत के बाद तैयार हुए इस संविधान को उसी दिन स्वीकार किया गया और यह दिन हमारे लोकतांत्रिक सफर की असली दस्तावेजी जन्मतिथि बन गया। बाद में 26 जनवरी को लागू करने के पीछे भी एक राजनीतिक और सांकेतिक निर्णय था, ताकि 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की याद के साथ गणराज्य की नई शुरुआत जोड़ी जा सके, इसलिए लागू होने की तारीख 26 जनवरी रखी गयी, जबकि अपनाने की ऐतिहासिक तारीख 26 नवम्बर ही रही।आज जो संविधान दिवस राजनीतिक बहस का केन्द्र है, वह दरअसल 2015 में एक नए रूप में सामने आया जब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर केन्द्र सरकार ने 26 नवम्बर को औपचारिक रूप से संविधान दिवस घोषित किया। इस निर्णय के पीछे तर्क यह था कि केवल गणतंत्र दिवस जैसे औपचारिक उत्सव से आगे बढ़कर साल में एक दिन ऐसा भी हो जो खास तौर पर नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद से हर वर्ष इस दिन विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों और सरकारी दफ्तरों में प्रस्तावना का सामूहिक पठन, गोष्ठियाँ, शपथ कार्यक्रम और बहसों का आयोजन होने लगा, जिसने इसे एक जीवंत राजनीतिक और सामाजिक उत्सव में बदल दिया। अब सवाल यह भी है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान में इतने सालों में कितने बड़े बदलाव आ चुके हैं और उनका स्वरूप क्या रहा है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसकी मजबूती का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि इसे समय के साथ बदलने और समाज की नई जरूरतों के अनुरूप ढलने की क्षमता दी गयी है। आज तक इसमें सौ से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से कई ने देश की राजनीतिक व्यवस्था, अधिकारों और शासन संरचना को गहरे तौर पर प्रभावित किया है; इन्हीं बड़े संशोधनों ने संविधान को केवल स्थिर दस्तावेज नहीं रहने दिया बल्कि एक जीवंत, बढ़ती हुई व्यवस्था में बदला है। इन बड़े परिवर्तनों में सबसे प्रमुख स्थान 42वें संशोधन को दिया जाता है, जिसे अक्सर 'लघु संविधान' कहा जाता है क्योंकि इसने प्रस्तावना से लेकर मूल कर्तव्यों और केन्द्र-राज्य संबंधों तक कई बुनियादी हिस्सों को बदल दिया। इसी संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गये और नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची पहली बार संविधान में दर्ज की गयी, जिससे अधिकारों के साथ कर्तव्यों की वैधानिक जिम्मेदारी भी रेखांकित हुई। यह संशोधन आपातकालीन दौर की राजनीति की देन था और आज भी इस पर बहस होती है कि इसने संविधान की मूल भावना को कितना मजबूत किया और कहाँ-कहाँ सत्ता के केंद्रीकरण का रास्ता खोला।44वें संशोधन ने उसी आपातकालीन दौर की कई अतियों पर प्रहार करते हुए मूल अधिकारों की रक्षा को फिर से मजबूत किया और आपातकाल की घोषणा जैसे प्रावधानों को अधिक कठोर और जवाबदेह बनाया। इस संशोधन के जरिये यह प्रयास किया गया कि भविष्य में सत्ता किसी एक व्यक्ति या दल के हाथ में अत्यधिक केंद्रित होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को कुचल न सके; यानी संविधान ने खुद अपने भीतर सुधार की प्रक्रिया अपनाकर लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए नई दीवारें खड़ी कीं। इसी क्रम में बाद के संशोधनों ने चुनावी व्यवस्था, पंचायती राज, नगर निकायों और आरक्षण नीति तक को नए रूप में गढ़ा। 73वें और 74वें संशोधनों ने गाँव से लेकर शहर तक स्थानीय स्वशासन की नई नींव रखी, जिससे पंचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला और आम नागरिक के दरवाजे पर लोकतंत्र की आवाजाही बढ़ी। इन संशोधनों ने महिला सहभागिता बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को मजबूती दी, जो बाद में राज्यों द्वारा अलग-अलग स्तर पर और विस्तारित की गयी; इस तरह संविधान ने लोकतंत्र को केवल राजधानी और विधानसभा भवनों तक सीमित नहीं रहने दिया बल्कि उसे मोहल्ले और गाँव की चौपाल तक पहुँचाया। इसी दौरान शिक्षा, नगर नियोजन और स्थानीय संसाधनों के नियंत्रण पर भी जनता और स्थानीय निकायों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में संवैधानिक सुरक्षा मिली।अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से जुड़े संशोधन भी संविधान में बड़े बदलाव के रूप में दर्ज हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाये गये। उच्चतम न्यायालय के फैसलों और राजनीतिक सहमति के बीच टकराव और समन्वय की कठिन प्रक्रिया से गुजरते हुए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को संतुलित किया गया, ताकि समता के आदर्श और प्रशासनिक दक्षता दोनों के बीच एक व्यावहारिक रास्ता निकल सके। हाल के वर्षों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने वाला संशोधन भी इसी बहस का हिस्सा है, जो दिखाता है कि संविधान की व्याख्या केवल जाति आधारित पिछड़ेपन तक सीमित नहीं रखी जा रही।इन सभी बड़े संशोधनों के बावजूद संविधान की प्रस्तावना में दर्ज न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल आदर्श आज भी वही हैं, जिन पर पूरी राजनीतिक बहस घूमती है। आज सत्ता पक्ष इन्हीं आदर्शों के नाम पर अपनी नीतियों को जनता के सामने न्यायोचित ठहराता है, तो विपक्ष भी इन्हीं आदर्शों का हवाला देकर सरकार पर हमला बोलता है कि कहीं न कहीं संवैधानिक संस्थाएँ कमजोर की जा रही हैं या अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। इसी टकराव में नागरिकों की भूमिका निर्णायक बनती है, क्योंकि लोकतंत्र में आखघ्रि फैसला मतदाता के हाथ में होता है, जो संविधान को अपने वोट से जिंदा रखता है।संविधान दिवस की राजनीति इसलिए भी अधिक तीखी हो गयी है क्योंकि यह दिन केवल उत्सव नहीं, आत्ममंथन का भी दिन बनता जा रहा है। आज जब संसद में बहस होती है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मीडिया की आजादी, चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता और संघीय ढांचे की मजबूती कितनी सुरक्षित है, तो उसका सीधा संबंध संविधान की आत्मा से जुड़ जाता है; कोई भी दल खुलकर यह स्वीकार नहीं कर सकता कि वह संविधान से ऊपर है, इसलिए सब उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। यही संविधान की असली ताकत है कि हर दल, हर नेता, हर आंदोलन को अंततः उसी किताब का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें पहली पंक्ति जनता को सर्वोच्च बताती है। आज भी जब संसद के बाहर नारों, टीवी बहसों और सामाजिक माध्यमों पर आरोप-प्रत्यारोप का शोर गूंजता है, तब भी संविधान की प्रस्तावना शांत, स्पष्ट और अडिग खड़ी रहती है। यह दिन याद दिलाता है कि सरकारें आयेंगी, जायेंगी, बहुमत बदलेंगे, नारे बासी हो जायेंगे, लेकिन अगर नागरिक सचेत रहें, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें, तो संविधान किसी भी तानाशाही इरादे को मात दे सकता है। इसी चेतना को जिंदा रखना ही संविधान दिवस का असली उद्देश्य है, और यही वजह है कि इस दिन की राजनीति जितनी गरम होगी, जनता के लिए संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती जाएगी।

-संजय सक्सेना,वरिष्ठ पत्रकार

आरक्षण के लिए ब्राह्मण-बेटियों की बेहूदी मांग

मध्य-प्रदेश में आईएएस अधिकारी का आचरण आदर्श व्यवहार के प्रति नितांत अभद्र बयान के रूप में सामने आया है। यह बयान केवल ब्राह्मणों की बेटियों के लिए ही नहीं, बल्कि समूचे देश की बेटियों के प्रति जातिसूचक अशोभनीय बयान है, जो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। राजधानी भोपाल में कृषि विभाग में उपसचिव स्तर के आईएएस संतोश वर्मा ने आरक्षण का पक्ष लेते हुए विवादित बयान में ब्राह्मण समाज की बेटियों को लपेटा है। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न कर दे या उससे संबंध न बना ले तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। केवल आर्थिक आधार की बात है तो जब तक रोटी-बेटी का व्यवहार नहीं होता, तब तक सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की पात्रता बनी रहनी चाहिए। वर्मा ने यह टिप्पणी मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिकारी तथा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक सभा में कही है। इस कथन का वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद इसका विरोध न केवल ब्राह्मणों ने किया, बल्कि सभी जातियों के प्रभुत्व नागरिकों ने भी किया है। इस आक्रोश के बाद संतोश वर्मा को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया। लेकिन इस बयान के बाद संतोष वर्मा के राज्यसेवा में रहते हुए काले-चिट्ठे का सिलसिलेवार खुलना शुरू हो गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि अनेक आपराधिक कृत्यों का आरोपी आखिरकार उस भाजपा सरकार में सेवा में कैसे है, जो नारियों के सम्मान की चिंता का दावा करने से अघाती नहीं है। उनकी आईएएस हेतु पदोन्नति पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस टिप्पणी के आद संतोष वर्मा बैकफुट पर तो है। उनके दुराचरण और फर्जीवाड़े की नई-नई परतें रोजाना खुल रही हैं। उन्होंने आईएएस की पदोन्नति के लिए विषेश न्यायाधीश विजय रावत के नाम से जाली आदेश व हस्ताक्षर तैयार कराए। इन दस्तावेजों और आदेश की सत्यापित प्रति के आधार पर उन्होंने खुद को बरी दिखाकर आईएएस कैडर और पदोन्नति हासिल कर ली। जबकि जिस दिन का यह आदेश है, उस दिन विजय रावत छुट्टी पर थे। जांच में यह आदेश फर्जी पाया गया। उन पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई। 27 जून 2021 को पुलिस ने वर्मा को गिरफ्तार किया और राज्य शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया। उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 471, (कूटरचित दस्तावेज) और 120-बी (साजिश) में मामला दर्ज है। इस प्रकरण की एसीपी सेंट्रल कोतवाली में अभी भी जांच चल रही है। संतोश वर्मा पर इंदौर के लसूडिया थाने में एक महिला ने धोखाधड़ी और शारीरिक शोशण की एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़ित महिला का कहना था कि वर्मा ने शादी का झांसा देकर विश्वासघात किया। वह पहले से ही विवाहित था। जिसे उसने छिपाया और बाद में शादी से मना कर दिया। इस पर महिला ने एफआईआर के साथ कई जगह सरकार को शिकायती पत्र भी लिखे। लेकिन राज्य सरकार न केवल चुप्पी साधे रखी, बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए पदोन्नत करने की अनुशंसा भी कर दी। सरकार का यह नितांत गैर-जुम्मेवाराना काम रहा था। इस पदोन्नति से संतोश वर्मा का अहंकार बड़ा और उन्होंने आरक्षण के बहाने ब्राह्मण बेटियों पर जिस तरह की निंदनीय टिप्पणी की, उसकी उम्मीद किसी समझदार व्यक्ति से कतई नहीं की जा सकती है ? यहां प्रश्न यह भी उठता है कि जिस अधिकारी को सेवा आचरण नियमावली तक का ज्ञान नहीं है, उसे कैसे सरकार ने आईएएस बना देने की अनुशंसा भारत सरकार को कर दी ? ऐसी दूषित मानसिकता के अधिकारियों से निष्पक्ष कार्यशैली की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती है ? अतएव राज्य सरकार को निलंबन से आगे जाकर सेवा समाप्ति की कार्यवाही तो करने की जरूरत तो है ही, पुलिस एवं अदालत में लंबित प्रकरणों पर भी बस्ते में बंद जांच आगे बढ़ाने की भी जरूरत है। मध्यप्रदेश में उच्चाधिकारियों के व्यवहार में उद्दंडता लंबे समय से बनी चली आ रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार के दौरान राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर में संशोधित नागरिकता कानून के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं को जिलाधीश और उप-जिलाधीश ने चांटे जड़ दिए थे। ये चांटे कलेक्टर निधि निवेदिता और डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा ने मारे थे। दोनों नौकरशाहों ने महज अहंकार तुश्टि के चलते कार्यकर्ताओं के साथ निरंकुशता बरती थी। इन दोनों अधिकारियों का यह आचरण नागरिक सेवा के विपरीत था। उनके द्वारा स्वयं भीड़ में पहुंचकर मारपीट करना दंडनीय अपराध है। जेएनयू से शिक्षित और ब्रिटिश हुकूमत के दंभ से प्रेरित यही निधी 2016 में सिंगरौली जिला पंचायत की सीईओ रहते हुए एक पंचायत सचिव को उठक-बैठक लगवा चुकी थी। जिला प्रमुख के 'कलेक्टर' नाम से वह अर्थ और ध्वनि नहीं निकलते हैं, जो उनकी कार्यशैली और कार्य क्षेत्र का हिस्सा है। कलेक्टर का सामान्य अर्थ, संग्राहक, संग्रहकर्ता, संकलनकर्ता, एकत्रित करने वाला अथवा कर उगाहने वाला होता है। जबकि हमारे यहां पदनाम का दायित्व जिले की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक दायित्व से जुड़ा है। इसलिए कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात जिला दण्डाधिकारी भी कहा जाता है। कलेक्टर को जिलाधिकारी अथवा जिलाधीश के पदनामों से भी जाना जाता है, किंतु कलेक्टर पदनाम इतना प्रचलित और प्रभावशील हो गया है कि जो भी आईएएस बनते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा गौरव का अनुभव कलेक्टर बनने या कलेक्टर कहलाने में ही होता है। इस बीमार प्रशासनिक तंत्र को दुरुस्त करने के लिए उनकी सेवा-शर्तों को नए सिरे से परिभाशित करने की जरूरत है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बीते दो दशकों के भीतर शासन-प्रशासन के स्तर पर कार्यशैली की गुणवत्ता में बहुत गिरावट आई है और हर क्षेत्र में प्रशानिक निरंकुशता बढ़ी है। शासन यानी सरकार का काम जन-हितैशी व चतुर्मुखी विकास संबंधी ठोस नीतियां बनाना है। स्वीकृत परियोजना के अनुरूप क्रियान्वयन का दायित्व प्रशासनिक अधिकारियों का होता है, जिनमें कलेक्टर जिला प्रमुख होने के साथ अधिकतम अधिकारों से संपन्न भी होता है। इसलिए 95 प्रतिशत कार्यों का संबंध ऐसे उचित क्रियान्वयन से है, जो पूरी तरह नागरिक सेवा के अधिकारियों के हाथ होता है। सच्चाई तो यह भी है कि विधायिका की बजाय अधिकांश नई नीतियों और नए कानूनों के निर्माण में भी अहम भूमिका इन्हीं अधिकारियों की रहती है। इसलिए ज्यादातर कानून इस तरह से परिभाशित किए जाते हैं कि उनमें अंतिम निर्णय का अधिकार अंततः अधिकारी के ही हाथ में रहे। पंचायती राज, सूचना का अधिकार, कानून और उपभोक्ता अदालतों से जनता का मोहभंग हो जाना यही प्रमुख वजह है। जब शिक्षा-तंत्र पर निगरानी की पहल का दायित्व पंचायतों को सौंपने की बात उठी थी, तब शिक्षकों ने बौद्धिक दंभ दिखाते हुए कहा था कि एक निरक्षर सरपंच उन पर निगरानी कैसे कर सकता है ? यह प्रश्न अपनी जगह तार्किक हो सकता है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में गौरतलब है कि शिक्षक रोजाना विद्यालय आता है अथवा नहीं ? आता भी है तो वह मटरगश्ती करता है या कुछ पढ़ाता भी है ? इसकी तस्दीक करने का संबंध निगरानीकर्ता के पढ़े-लिखे होने से कतई नहीं है ? आज सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण पढ़ाई से बड़ा सवाल शिक्षक का विद्यालय में उपस्थित नहीं होना है। अब भला शिक्षक की उपस्थिति की तस्दीक करने में निरक्षरता कहां बाधा बनती है ? यहां यह भी गौरतलब है कि एक अनपढ़ व्यक्ति का व्यावहारिक ज्ञान, पढ़े-लिखे से भी कहीं ज्यादा भी हो सकता है ? कलेक्टर हो या कोई अन्य लोकसेवक उसकी गुणवत्ता का मापदण्ड, उसकी ईमानदारी, कार्यक्षमता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता से होती है। नीतियों व कार्यों पर यदि ठीक से अमल नहीं होता है तो गुणवत्ता ध्वस्त हो जाती है। प्रत्येक राज्य सरकार अनेक श्रेश्ठ नीतियां गरीब, वंचित और किसानों के हित में बनाती हैं, लेकिन प्रशासनिक अकुशलता और भ्रश्टाचार के चलते परिणाम के स्तर पर अमल दोशपूर्ण रहता है। यही वजह रही कि मध्य-प्रदेश में क्लर्क से लेकर आईएस तक जिन अधिकारियों के यहां लोकायुक्त पुलिस ने छापे डाले हैं, उनके यहां से करोड़ों की चल-अचल संपत्तियां बरामद हुई हैं। रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद ये लोकसेवक धनबल व अपनी पहुंच के जरिए बेदाग बच निकलते हैं। इनका बच निकलना इसलिए भी आसान होता है, क्योंकि बचाव के पक्ष में अनेक कानून और अनुमोदन की कड़ियां हैं। किसी नौकरशाह को गिरफ्त में लेने से पहले इन कड़ियों से पार पाना टेढ़ी खीर होता है। बावजूद कोई भी संवेदनशील सरकार इतना तो कर ही सकती है कि भ्रश्टाचार के मामले में पकड़े गए और तकनीकी आधार के बूते छूटे लोकसेवकों को प्रशासनिक दायित्व से मुक्त रखे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह संतोश वर्मा के मामले में भी साफ दिखाई दे रहा है।

-प्रमोद भार्गव,वरिष्ठ पत्रकार

बोर्ड बैठक में विकास कार्यों से जुड़े 11 प्रस्तावों को मंजूरी

शक्तिफार्म। नगर पंचायत शक्तिगढ़ में शुक्रवार को आयोजित बोर्ड बैठक में विकास कार्यों से जुड़े 11 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। बैठक की अध्यक्षता नगर पंचायत चेयरमैन सुमित मंडल ने की। इस दौरान सभासद सुनीता सरकार, सुशीला राय, विक्रम भंडारी, मीना देवी, शीला पोद्दार, सुबीर सरकार और गोविंद सरकार मौजूद रहे। प्रभारी अधिशासी अधिकारी प्रियंका रैकवाल ने बताया कि नगर में कूड़ा निस्तारण के लिए भूमि की लीज अवधि बढ़ाने, सोलर लाइट लगाने, सफाई व्यवस्था को मजबूत करने हेतु ई-रिक्शा क्रय करने, मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर उपलब्ध कराने, व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, विभिन्न वार्डों के मंदिरों का सौंदरीकरण तथा मोबाइल टॉयलेट क्रय करने सहित कई प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। बोर्ड ने नगर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए व्यापार मंडल के साथ वार्ता कर विशेष अभियान चलाने का निर्णय भी लिया। साथ ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति और निर्माण कार्यों की ठेकेदारी के पंजीकरण से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई। बैठक में लिए गए इन निर्णयों से नगर में स्वच्छता, रोशनी और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को 13 पीजी कोर्स की मंजूरी

अल्मोड़ा। नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को 13 नए पीजी कोर्स शुरू करने की अनुमति प्रदान की है। मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के जारी लेटर आफ परमिशन के अनुसार कॉलेज को कुल 33 नई सीटों की स्वीकृति मिली है, जो आगामी सत्र से प्रभावी होगी। एनएमसी की टीम ने कॉलेज का भौतिक निरीक्षण, फैकल्टी उपलब्धता, अस्पताल सुविधाएं, क्लीनिकल सामग्री और उपकरणों की जांच की। मूल्यांकन प्रक्रिया में कॉलेज सभी मानकों पर संतोषजनक पाया गया। इसके बाद एमएआरबी ने मंजूरी जारी की। एनएमसी ने स्पष्ट किया है कि कॉलेज को पूरे सत्र में गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा। गलत जानकारी या दस्तावेजों में गड़बड़ी पाए जाने पर अनुमति तुरंत निरस्त कर दी जाएगी। वहीं, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए यह मंजूरी कुमाऊं क्षेत्र की उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं व विशेषज्ञ डाक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है। पीजी कोर्सों में एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन दो, एमडी पीडियाट्रिक्स चार, एमडी/एमएस एनाटॉमी तीन, एमएस ऑर्थोपेडिक्स दो, एमडी एनेस्थीसियोलॉजी तीन, एमएस ऑप्थैल्मोलाजी दो, एमएस ऑब्स एंड गायनेकोलाजी दो, एमडी जनरल मेडिसिन दो, एमडी फिजियोलाजी तीन, एमडी माइक्रोबायोलॉजी तीन, एमडी पैथोलॉजी तीन, एमडी फार्माकोलॉजी तीन, एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन व टॉक्सिकोलॉजी तीन सीटे शामिल हैं। प्रो. सीपी भैसोड़ा, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के अनुसार एनएमसी की ओर से 13 पीजी कोर्सों को स्वीकृति प्रदान की गई है। जल्द मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स शुरू होगा। वहीं, अब विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर होगी।

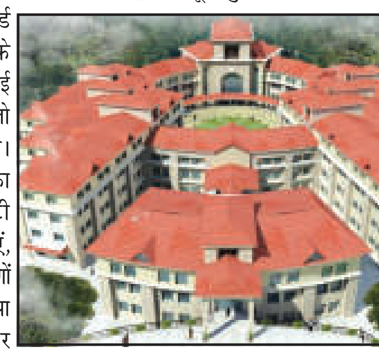

विकास कार्यों की अनदेखी पर निगम में सोमवार को दूंगा धरना-मुंजाल

रुद्रपुर। अलायंस वार्ड में विकास कार्यों की लगातार अनदेखी और पार्षद द्वारा बोर्ड बैठक में दिए गए प्रस्तावों पर कार्रवाई न होने के विरोध में पार्षद प्रतिनिधि सचिन मुंजाल ने सोमवार को नगर निगम परिसर में धरने का ऐलान किया है। वह सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से निगम परिसर में अपनी बात रखेंगे। सचिन मुंजाल ने आरोप लगाया कि उनके वार्ड में विकास कार्यों की अपेक्षित गति नहीं है और कई महत्वपूर्ण कार्य लंबे समय से रुके हुए हैं। उन्होंने बताया कि भूरारानी मार्ग और गेट द्वार का नाम परिवर्तित किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि हाल ही में इस मार्ग का नाम बदलने का प्रस्ताव किया गया, जो उचित नहीं हैं। मुंजाल ने कहा कि बोर्ड मीटिंग में पार्षद द्वारा प्रस्तुत कई प्रस्ताव अब तक लागू नहीं किए गए, जिससे वार्ड के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह शांतिपूर्ण, सम्मानजनक और संवेदनशील ढंग से अपना विरोध दर्ज कराएंगे।

पारिवारिक विवाद में दर्जी ने अपने पेट में मारी कैंची, मौत

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। राजपुरा क्षेत्र के राजेंद्र नगर में पारिवारिक विवाद में सिलाई का काम करने वाले व्यक्ति ने घर गुरुवार को अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। चाकू लेकर दौड़ाया तो बेटे ने बीच बचाव कर उससे चाकू छीन लिया। इससे गुस्साए राकेश ने दुकान से कैंची लेकर खुद के पेट पर तीन वार कर लिया। एसटीएच में इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह चार बजे के उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार दर्जी राकेश दुकान से घर आने के बाद राकेश अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगे। विवाद बढ़ने पर उसने पत्नी पर चाकू हमला किया। यह देख बेटे ने बीच-बचाव कर पिता के हाथ से चाकू छीना। इसके कुछ समय बाद राकेश अपनी दुकान पर पहुंचा और बड़ी कैंची लेकर घर आया। इसे देखकर घबराई पत्नी ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया।लोगों के अनुसार राकेश शराब के नशे में था और उसने कैंची से अपने ही पेट पर तीन वार कर लिया। जिससे वह लहुलुहान होकर वहीं गिर गया। उसे आनन-फानन बेस अस्पताल ले जाया गया। वहां से एसटीएच रेफर किया गया। शुक्रवार की सुबह उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। कोतवाली के एसएसआई रोहिताश सागर ने बताया कि मौके पर फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य एकत्र किया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया गया।

रिसेप्शन में मेकअप को लेकर हुआ विवाद,कई लोग चोटिल

शक्तिफार्म। शादी के बाद आयोजित रिसेप्शन पार्टी में दुल्हन के मेकअप को लेकर हुई कहासुनी बड़ा हंगामा बन गई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के कई लोग चोटिल हो गए। नाराज दुल्हन पक्ष बाद में नवविवाहित दुल्हन को अपने साथ लेकर विवाह स्थल से लौट गया। जानकारी के अनुसार, क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक का नानकमत्ता निवासी युवती से विवाह हुआ था। बुधवार को दूल्हे के घर पर रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें नानकमत्ता से दुल्हन पक्ष के परिजन भी पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान दुल्हन पक्ष की एक महिला रिश्तेदार ने दुल्हन के मेकअप को खराब बताते हुए दूल्हे के परिजनों पर टिप्पणी कर दी। इस टिप्पणी से दूल्हा पक्ष आक्रोशित हो गया और देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। हंगामे में दोनों ओर के कुछ लोग घायल भी हुए। स्थिति बिगड़ती देख दुल्हन पक्ष ने दुल्हन को वहीं से अपने साथ ले लिया। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

कच्ची शराब सहित महिला नशा तस्कर गिरफ्तार

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। ट्रांजिट कैम्प थाना पुलिस ने चौंकिंग के दौरान एक महिला नशा तस्कर को कच्ची शराब ले जाते गिरफ्तार कर लिया।जानकारी के अनुसार थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस टीम द्वारा चैंकिंग के दौरान कुलवंत कौर पत्नी मंजीत सिंह निवासी अंजनी विहार, फूलसुंगा को कच्ची शराब ले जाते पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से कट्टे में रखे कुल 63 पाउच लगभग 21 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस ने बरामद शराब कब्जे में लेकर कुलवंत कौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस टीम में उप निरीक्षक विकास रावत, अपर उप निरीक्षक चंद्र प्रकाश बावड़ी व महिला कांस्टेबल लीला आर्य शामिल थे।

घर में घुसकर माता पिता से की मारपीट

काशीपुर। पुरानी रंजिश के चलते एक युवक व उसके माता-पिता के साथ घर में घुसकर मारपीट के मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर डेढ़ माह बाद मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। न्यायालय को दिए प्रार्थना पत्र में थाना कुंडा के ग्राम चिन्तपुरी गढ़ीनेगी निवासी गुरजीत सिंह पुत्र मान सिंह ने बताया कि बीती 13 अक्टूबर 2025 की प्रात प्रार्थी अपने फौजी भाई बलविन्दर सिंह के बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस आने पर पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही प्रगट सिंह उर्फ लक्की, अवतार सिंह पुत्रगण सन्तोख सिंह, उषा पत्नी अवतार सिंह गुरप्रीत सिंह पुत्र जोगा सिंह ने एक राय होकर घर में घुसकर लाठी-डंडो मारपीट करते हुए उसे लहुलूहान कर दिया। साथ ही उसके माता-पिता के साथ भी मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

कुंडा क्षेत्र से युवती लापता, गुमशुदगी दर्ज

काशीपुर। कुंडा थाना क्षेत्र से एक युवती बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में लापता बताई जा रही है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज कर गायब युवती का पता लगाना शुरू कर दिया। पुलिस को तहरीर देकर मूल पोस्ट भटपुरा, थाना रेहड़ अफजलगढ़ जनपद बिजनौर व हाल हरियावाला कुंडा क्षेत्र निवासी महिला ने बताया कि उसकी 19 वर्षीय बहन 19 सितंबर की शाम लगभग 8:00 परिजनों को बगैर बताए कहीं चली गई। पुलिस को यह भी बताया गया कि तमाम संभावित स्थानों पर तलाश के बाद भी युवती का अब तक कहीं कोई पता नहीं चला।

खाईबाड़ी करता एक सट्टेबाज गिरफ्तार

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। बनभूलपुरा थाना पुलिस ने चौकिंग के दौरान एक सट्टेबाज को खाई बाड़ी करते हजारों की नगदी व सट्टा पर्ची आदि सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी थानाध्यक्ष सुशील जोशी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा चौकिंग के दौरान सट्टा खेलते हुए एक व्यक्ति खालिद उर्फ राजू पुत्र ताहिर निवासी लॉट नं. -18, वार्ड 25, बनभूलपुरा को दबोचा गया। जिसके कब्जे से सट्टा पर्चियाँ, 3320 रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस ने खालिद को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस टीम में उप निरीक्षक जगवीर सिंह, का.सुनील कुमार व दिलशाद अहमद शामिल थे।

पेज एक का शेष...

दिल्ली ब्लास्ट में ...कई घायल हुए थे। सरकार द्वारा इसे आतंकी हमला घोषित किए जाने के बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। लाल किले के बाहर 10 नवंबर को हुए कार बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आरोपी आमिर राशिद अली को पेश किया था। एनआईए ने दावा किया कि आरोपी ने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी को सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराया और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की थी। इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई थी।

समाज कल्याण का कार्य ही...के लिए किया गया कार्य ही सबसे बड़ा धर्म है। यह सन्देश सदा प्रेरणा देता है कि व्यक्ति को अपने लाभ, स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठकर निष्काम भाव से राष्ट्र और सम्पूर्ण मानवता के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन की प्रत्येक कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में यह एक अद्भुत, प्रेरणादायक श्लोक के रूप में मार्ग दर्शन करता है। श्री धामी ने कहा कि हम सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ऐसे छद्म वेशधारियों के खिलाफ भी आपरेशन कालनेमी के तहत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इस अभियान में हमने हजारों ऐसे पाखडियों और विधर्मियों को गिरफ्तार किया है जो सनातन धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऐसे कई घुसपैठिये भी हैं जो नाम और भेष बदलकर उत्तराखण्ड की पवित्र धरा को अपमानित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। हमारी सरकार इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए अपने दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। श्री धामी ने अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुये कहा कि उन्होंने लव जिहाद,लैंड जिहाद और धर्मान्तरण के खिलाफ कानून बनाया है। मदरसा बोर्ड खत्म करने का काम किया। अब वहा स्कूली पाठयक्रम को लागू किया है। 10 हजार एकड़ भूमि को लैंड जिहाद से मुक्त कराया और उनका यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। श्री धामी ने वर्ष 2027 में होने वाले कुंभ मेला में हरियाणावासियों को ससम्मान आमंत्रित किया। श्री धामी के कार्यक्रम में पहुंचने पर आयोजकों द्वारा उनका जोरदार स्वागत करते हुये उन्हे सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर,मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि और शंकराचार्य के साथ देश भर के कई संत मुख्य मंच पर मौजूद रहे और उन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया।

टक की टक्कर से ....सहित मौके से फरार हो गये। हृदय विदारक इस घटना पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने गहरा शोक प्रकट करते हुये परिजनों को ढांढस बंधाया। जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर के जगतपुरा निवासी शंकर मंडल जोकि एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। शुक्रवार को चंडीपुर स्थित विवाह समारोह में जा रहा था। बताया जा रहा है कि जैसे ही वह अपनी बाइक से गदरपुर-मटकोटा मार्ग पर पहुंचा, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने उसकी बाईक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही शंकर बाईक समेत सड़क पर गिर पड़ा और इससे पहले कि वह संभल पाता, पीछे से तेज गति से आ रही बस ने उसे बुरी तरह कुचल दिया। दुर्घटना इतनी भयावह थी कि शंकर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद ट्रक और बस चालक दोनों ही अपने वाहनों समेत मौके से फरार हो गए। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चौकी इंचार्ज जयनगर मनोज देव ने बताया कि ट्रक और बस की वजह से सड़क हादसे की बात सामने आ रही है। बस का नंबर लोगों के मोबाइल से फोटो खींचे जाने पर आ गया है। बाकी सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल भी पोस्टमार्टम पहुंच गये और घटना पर गहरा शोक प्रकट करते हुये परिजनों का ढांढस बंधाया और उन्हे हर सम्भव सहायता का आश्वासन दिया।

अपराधियों का गढ़...जाएगी। बताते है कि ठंडा नाला वो आपराधिक शरण स्थली है जहां उत्तराखंड ही नहीं यूपी,पंजाब के अपराधी संकरी गलियों में बने मकानों में पुलिस से छुपते थे और पुलिस यहां छापा मारने के दौरान शरण देने वालों के हमलों का सामना करती थी। प्रशासनिक कारवाई से पूर्व एसएसपी मणि कांत मिश्रा ने भी क्षेत्र का ड्रोन सर्वे करवाया और पुलिस फोर्स को कई सेक्टर बना कर तैनात करवाया। सीएम पीएस धामी ने बीते कल ये बयान दिया था कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।लैंड जिहाद के खिलाफ सरकार का प्रहार जारी है और जारी रहेगा।

रूद्रपुर नगर निगम..कहा, जब पार्षदों के पास बेहतर साधन होंगे, तो स्वाभाविक रूप से जनता को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। यह सुविधा जनता के हित में ही उठाया गया कदम है। नगर निगम की इस पहल को पार्षदों ने भी सराहा है। कई पार्षदों ने कहा कि मेयर का यह निर्णय उनकी दैनिक कार्यशैली को सरल और प्रभावी बनाएगा। वहीं शहरवासियों ने भी इसे एक स्वागतयोग्य कदम बताते हुए कहा कि इससे पार्षदों की उपलब्धता और जनता की समस्याओं का समाधान और भी तेजी से होगा।

चोरों ने बंद घर ...पुलिस को दी। मामले की जानकारी देते चौकी रूद्रविलास थाना बिलासपुर रामपुर क्षेत्रांर्गत गोपाल विहार निवासी महिपाल ने बताया कि वह एक कम्पनी में मार्केटिंग का काम करता है। वह अपनी बहन की शादी में परिवार सहित घर में ताला लगाकर गया था। शुक्रवार को उसके पड़ोसियों ने बताया कि घर के गेट का ताला खुला देख जब भीतर गये तो सारा सामान बिखरा पड़ा मिला है। सूचना मिलते ही वह घर वापस लौटा। उसने पाया कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ है और अलमारी भी खुली हुई है। महिपाल का कहना है कि चोर अलमारी में रखे करीब 5 लाख रूपये कीमत के जेवर और लगभग 70 हजार की नगदी सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गये हैं। महिपाल ने बताया उसने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है।

विद्युत चोरी में चार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

गदरपुर । विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम द्वारा छापामारी करते हुए तीन घरों में बिजली चोरी पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कराने की थाने में तहरीर दी है । प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्युत विभाग की विजलेंस टीम के ए ई पुनीत कुमार द्वारा वार्ड नंबर 3 में छापामारी करते हुए चार घरों में विद्युत चोरी होता पाया गया जिनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु प्राथमिकी दर्ज कराई गई है । टीम में जे ई सुभाष आर्य, हरजीत सिंह, लाइनमैन नंदू मलिक एवं हरीश कुमार शामिल थे ।

संस्थापक-स्व० हरनामदास सुखीजा एवं स्व०तिलकराज सुखीजा
स्वामित्वाधिकारी,प्रकाशक एवं मुद्रक परमपाल सुखीजा द्वारा उत्तरांचल दर्पण पब्लिकेशन्स, श्याम टाकीज रोड,रुद्रपुर,ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड)से मुद्रित एवं प्रकाशित
सम्पादक- परमपाल सुखीजा
आरएनआई नं.: UTTHIN/2002/8732 समस्त विवाद रूद्रपुर न्यायालय के अधीन होंगे।
E-mail-darpan.rdr@gmail.com,www.uttaranchaldarpan.in
फोन-245886(O)245701(Fax),9897427585,9897427586(Mob.)

किच्छा में प्राधिकरण कर रहा एकपक्षीय कार्रवाई–बेहड़

किच्छा। विकास प्राधिकरण द्वारा सिरौली में बगैर नक्शा पास कराए गए भवनों के खिलाफ चलाए गए अभियान के विरोध में आज विधायक तिलकराज बेहड़ द्वारा स्थल निरीक्षण कर जायजा लिया गया उन्होंने विकास प्राधिकरण द्वारा शुक्रवार को तोड़ी गई सड़क सहित करके माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ही रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है उन्होंने यह भी कहा कि जनपद उधम सिंह नगर में हर जगह जगह पर जमीन खरीद फरोख्त हो रही है केवल प्रशासन ने सिरौली को ही टारगेट किया हुआ है यह में पहुंचे और वहां विकास प्राधिकरण द्वारा की गई शुक्रवार की कार्यवाही का निरीक्षण कर आम नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि वह इस मामले को सरकार में पक्ष रखेंगे तथा किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होने देंगे उन्होंने प्रशासन को आड़े के बाद भी केवल मानचित्र पास न होने पर ध्वस्ति करण जैसी कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण को पहले प्रत्येक व्यक्ति को नोटिस देकर के उसको समय अवधि देनी चाहिए तथा मानचित्र पास करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए समर्थन नहीं कर रहेभाई है किंतु जहां लोग अब निवास कर रहे हैं उनके मकानों को तोडना या उन्हें बेघर करना यह मानवता का धर्म नहीं है उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस प्रकार के किसी भी कार्यवाही का विरोध किया जाएगा तथा नागरिकों के हितों की लड़ाई लड़ी मानवता को दिखाते हुए कार्य करना अति आवश्यक है उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मकान बना लिए हैं उन्हें मानचित्र बनाने के लिए अप्लाई करने का समय दिया जाना चाहिए तथा मानचित्र पास करते हुए लोगों को राहत दी जानी चाहिए। इस अवसर पर मुख्य

तोड़े गए मकान का भी जायजा लिया उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही की जा रही है जो की गलत है उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन समुदाय विशेष पर कार्यवाही नेता विशेष एवं पार्टी विशेष के निर्देश पर हो रहा है वह किसी प्रकार का भी शोषण नहीं होने देंगे। शनिवार प्रात: पूर्व विधायक कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्रीय विधायक तिलक राज बेहड़ सिरौली क्षेत्र हाथों लेते हुए कहा कि जब भवनों का निर्माण हो रहा था उस समय अधि कारियों द्वारा उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया उन्होंने यह भी कहा कि कुछ भवनों की रजिस्ट्री दाखिल खारिज होने उन्होंने कहा कि जिन भवनों का निर्माण हो चुका है उनका मानचित्र बनाने की प्रक्रिया को अमल में लाकर के कार्रवाई की जानी चाहिए थी उन्होंने यह भी कहा कि वह अनऑथराइज्ड कॉलोनी के जाएगी उन्होंने यह कहा कि कुछ लोगों के इशारे पर जो कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है वह उचित नहीं है सरकारी आती है जाती हैं किंतु प्रशासन वही रहता है इसलिए प्रशासन को भी रूप से गुलशन सिंधी ओमप्रकाश पप्पू राजेश प्रताप सिंह दर्शन सिंह कोली, एन यू खान कांग्रेस नगर अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, अरुण कुमार शुक्ला उर्फ किन्नू शुक्ला, मिस्वाल कुरैशी, साहित्य मौजूद थे।

अंग्रेजी शराब की खेप के साथ एक आरोपी गिरफ्तार

हल्द्वानी। ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत नैनीताल पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से अवैध अंग्रेजी शराब की भारी खेप बरामद की है। एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशन पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पुलिस टीम ने एक शराब तस्कर को 25 पेटी प्रतिबंधित शराब के साथ गिरफ्तार किया। पकड़ी गई शराब की बाजार कीमत लगभग छह लाख रुपये बताई जा रही है। एसपी सिटी हल्द्वानी मनोज कत्याल के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी अमित कुमार सैनी के पर्यवेक्षण में कोतवाली प्रभारी रोहिताश सागर तथा चौकी प्रभारी भोटियापड़ाव उपनिरीक्षक अनिल कुमार की टीम ने शहर में चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान XUV700 (UK-

04 AJ-7676) को रोककर की गई तलाशी में वाहन से रेड लेबल, जेम्सन, बैलेंटाइन और ब्लॉन्ड ब्रांड की कुल 25 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सिमरन प्रीत (उम्र 36 वर्ष), निवासी गोविंदपुरा सुभाषनगर, हल्द्वानी के रूप में हुई है, जो स्थानीय स्तर पर बाइक मैकेनिक की दुकान चलाता है। पुलिस के अनुसार आरोपी अवैध शराब हरियाणा से हल्द्वानी लाया था। उसके खिलाफ कोतवाली हल्द्वानी में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उसके आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक अनिल कुमार, उपनिरीक्षक रेनू सिंह और कांस्टेबल दिनेश नगरकोटी शामिल रहे।

एस आई आर को लेकर राजनीतिक दलों के साथ प्रशासन की बैठक

गदरपुर(उद संवाददाता)। गदरपुर तहसील परिसर में बंगाली कल्याण समिति की क्षेत्र के तमाम राजनीतिक दल के लोगों के साथ एसडीएम ऋचा सिंह की अध्यक्षता में एसआईआर को लेकर बैठक की गई। बैठक में एसडीएम द्वारा एसआईआर के बारे में जानकारी दी। जिसमें जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है उनका ऑटोमेटिक ग्रीन किया जा रहा है। जिनका नहीं है उनको माता–पिता दादा–दादी जिन्होंने 2003 में वोट दिया हो भारत के किसी भी कोने में रहते हो 2003 वोटर लिस्ट लानी होगी। उन्होंने बताया कि जिस लड़की की शादी हो गई उसे अपने मायके से 2003 की वोटर लिस्ट लानी

होगी। उनका नाम चढ़ जाएगा। इस काम के लिए जनता की तरफ से हर बूथ पर दो जनता की तरफ से बीएलओ की नियुक्ति करनी है। जिससे जनता को राहत मिल सको एसडीएम ने कहा कि यह सतत् प्रक्रिया है। 10 साल में होती है पर इस बार 20 साल में हो रही है इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। लोग अपने बीएलओ के पास जाकर अपना नाम चेक करें। समिति के वक्ताओं ने कहा कि किसी तरह से दिक्कत आने पर बंगाली कल्याण समिति सबके साथ है। बैठक में बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश महामंत्री नारायण हालदार, तिलक राज गंभीर समेत तमाम राजनीतिक दल के लोग मौजूद रहे।

नागा रेजिमेंट के रिटायर्ड कैप्टन भवान सिंह का निधन

रुद्रपुर (उद संवाददाता) भारतीय सशस्त्र सेन नागा रेजीमेंट से रिटायर्ड कैप्टन भवान सिंह रौथाण ने मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में आज अंतिम सांस' ली। उनके फेफड़ों में पानी भरने अंदरुनी जख्म हो जाने से वह काफी समय से पीड़ित

थे।भारतीय सशस्त्र सेना नागा रेजीमेंट से रिटायर्ड कैप्टन 62वर्षीय भवान सिंह रौथाण पुत्र स्वर्गीय माधौ सिंह रौथाण निवासी खटोला, दिनेशपुर का लंबी बीमारी के बाद आज मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में निधन हो गया है। उनका विगत 4 माह से इलाज चल रहा था ।जो कि पहले मेडिसिटी अस्पताल रुद्रपुर मे 17 दिन उपचारधीन रहे। मेडिसिटी अस्पताल के डाक्टर द्वारा मशीने ना होने का हवाला देते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिए जाने के बाद रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज मैं उपचार करने के पश्चात 22 सितंबर को मेदांता अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। जहां आज उनका निधन हो गया है। जिनके पार्थिव शरीर को आज देर रात्रि उनके ग्रह निवास दिनेश पुर लाया जाएगा। कल 30 नवम्बर को चित्राशिला घाट, रानीबाग मे अंत्येष्टि की जाएगी । भवान सिंह रौथाण ने वर्ष 1997 में ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध के दौरान मैं अग्रणी भूमिका निभाई थी ।

रूद्रपुर के घायल युवक ने बरेली में तोड़ा दम

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। 23 नवम्बर को बाजपुर में आयोजित एक विवाह समारोह में गये रूद्रपुर रम्पुरा निवासी 15 वर्षीय सचिन कोली को छत से धक्का देकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। जिसका राममूर्ति अस्पताल में उपचार हो रहा था गत दिवस उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। उसका शव उसके आवास पहुंचने पर परिजनों में कोहराम मच गया। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने मृतक सचिन कोली पुत्र

पप्पू कोली के निवास वार्ड 24 पहुँच कर पीड़ित परिवार को ढाँढस बंधाया। गौरतलब हो कि सचिन कोली 23 नवम्बर को बाजपुर रिश्तेदारी की शादी में बाजपुर गया था। जहां लड़की पक्ष के युवकों से उसका किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद उन्होंने सचिन से मारपीट कर उसे छत से नीचे फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल सचिन को उपचार के लिए राममूर्ति अस्पताल बरेली भर्ती कराया गया था। जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बाजपुर पुलिस द्वारा इस मामले में प्रकाश सहित दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।